

उदयनिधि का सनातन विरोधी बयान विभाजनकारी: विहिप



नई दिल्ली । विश्व हिन्दू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने तमिलनाडु विधानसभा में उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी वक्तव्य की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि क्या इस प्रकार का वक्तव्य किसी अन्य मजहब के विरुद्ध भी देने का साहस कर सकते हैं? सनातन धर्म और उसकी आस्थाओं को निरंतर अपमानित करना लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के भी विपरीत है। नेता विपक्ष के बयान को अविलंब विधानसभा की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए।

थाली में छेद करने जैसी मानसिकता

उन्होंने कहा कि अत्यंत विडंबनापूर्ण स्थिति है कि जिन परिवारों और राजनीतिक दलों को स्वयं सनातन परंपराओं, मंदिरों और हिन्दू समाज से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष लाभ प्राप्त होता है, वही लोग सनातन को समाप्त करने की बातें कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार को राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों और सनातन परंपरा से जुड़े धार्मिक स्थलों से पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता है, इसके बावजूद सनातन विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन करना उसी थाली में छेद करने जैसा है।

आलोक कुमार ने कहा कि तमिलनाडु के नवीन मुख्यमंत्री को भी इस विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि उनकी सरकार सनातन परंपरा और हिन्दू आस्थाओं के सम्मान के पक्ष में है अथवा वह ऐसे विभाजनकारी और दुर्भावनापूर्ण हिन्दूद्वेषी वक्तव्यों का समर्थन करती है।

वक्तव्य को विधानसभा कार्यवाही से हटाने की मांग

उन्होंने मांग की कि इस प्रकार के घोर आपत्तिजनक और विभाजनकारी वक्तव्य को विधानसभा की कार्यवाही से तत्काल हटाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँ। विहिप अध्यक्ष ने कहा कि-सनातन हिन्दू धर्म तमिलनाडु सहित पूरे भारत की सांस्कृतिक आत्मा है। इतिहास साक्षी है कि सनातन को समाप्त करने का प्रयास करने वाली अनेक विचारधाराएँ स्वयं समाप्त हो गईं, किंतु

मोदी कैबिनेट ने गैस संकट को दूर करने के लिए उठाया बड़ा कदम देश में अब कोयले से बनेगी गैस

■ खरीफ फसलों का स्वतक बढ़ाने को भी मंजूरी दी

नई दिल्ली। वर्तमान वैश्विक चुनौतियों और गैस आपूर्ति को लेकर पैदा हो रहे संकट के बीच मोदी सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलते हुए देश के विशाल कोयला भंडार को ऊर्जा आत्मनिर्भरता का आधार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कोयले से गैस बनाने की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी गयी। सरकार का मानना है कि अगले चार से पांच वर्षों में बड़े पैमाने पर कोयले से गैस का उत्पादन शुरू होने पर भारत गैस के मामले में आत्मनिर्भर बन सकेगा और उसे वर्तमान जैसी वैश्विक आपूर्ति चुनौतियों तथा आयात निर्भरता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज

लिये गये फैसलों की जानकारी संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिये 37 हजार 500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 10 करोड़ टन कोयले के गैसीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य को गति देना है। इसके तहत लगभग 7 करोड़ 50 लाख टन कोयला और लिग्नाइट के गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और एलएनजी, यूरिया, अमोनिया तथा मेथानल जैसे उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम होगी। योजना के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी लागत का अधिकतम 20 प्रतिशत तक प्रोत्साहन दिया जायेगा। किसी एक परियोजना के लिये



पांच हजार करोड़ रुपये तक की सीमा तय की गयी है। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि गैसीकरण परियोजनाओं के लिये कोयला आपूर्ति अवधि को बढ़ाकर 30 वर्ष किया जायेगा ताकि निवेशकों को दीर्घकालिक स्थिरता मिल सके। इस योजना से लगभग ढाई से तीन लाख करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना है और करीब

50 हजार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। सरकार के अनुसार इससे राज्यों को हर वर्ष लगभग छह हजार 300 करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त होगा।

मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के लिये 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गयी। सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। सूरजमुखी के बीज के समर्थन मूल्य में सबसे अधिक 622 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गयी है। इसके बाद कपास में 557 रुपये, रामतिल में 515 रुपये और तिल में 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गयी है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2441 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अरहर का समर्थन मूल्य 8450 रुपये, मूंग का 8780 रुपये और उड़द का

8200 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकार ने कहा कि वर्ष 2018-19 के बजट में किये गये वादे के अनुरूप किसानों को उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना मूल्य सुनिश्चित किया जा रहा है। मूंग पर किसानों को लागत से 61 प्रतिशत, बाजरा और मक्का पर 56 प्रतिशत तथा अरहर पर 54 प्रतिशत लाभ मिलने का अनुमान है। सरकार ने यह भी बताया कि वर्ष 2014-15 से 2025-26 के दौरान धान खरीद 8418 लाख टन रही, जबकि इससे पहले के दस वर्षों में यह 4590 लाख टन थी। इसी अवधि में खरीफ फसलों पर किसानों को लगभग 19 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गुजरात में अहमदाबाद के सरखेज से धोलेरा तक सेमी हाई स्पीड डबल रेल लाइन परियोजना को भी मंजूरी दी।



रायपुर। सुशासन तिहार के अंतर्गत शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के विकासखंड अंबागढ़ चौकी के ग्राम पंचायत हांडीटोला में गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक न्याय की थीम पर दिव्यांगजनों को समर्पित समाधान शिबिर का आयोजन किया गया। शिबिर में विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीणों की समस्याएँ सुनी गईं तथा पात्र हितग्राहियों को मौके पर योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

अमूल दूध 2 रुपए लीटर महंगा हुआ



नई दिल्ली। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी बुधवार को दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। दोनों कंपनी के नए दाम गुरुवार (14 मई) से लागू होंगे। अमूल और मदर डेयरी ने दूध के प्रमुख वैरिएंट और पैक पर कीमतें बढ़ाई हैं।

गुजरात कॉर्पोरेट मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मुताबिक, पशु आहार, पैकेजिंग और ईंधन की लागत बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया। अमूल का कहना है कि यह बढ़ोतरी 2.5% से 3.5% के बीच है। अमूल ने मई 2025 के बाद पहली बार दूध के दाम बढ़ाए हैं। वहीं मदर डेयरी ने इससे पहले दूध की कीमतों में अप्रैल 2025 में बढ़ोतरी की थी। को-ऑपरेटिव के मुताबिक, दूध के प्रोडक्शन और ऑपरेशनल खर्च में लगातार

■ आधे घंटे बाद मदर डेयरी ने भी ?2 लीटर रेट बढ़ाए, नए दाम आज से लागू होंगे

बढ़ोतरी हो रही है। पशु चारे की बढ़ती कीमत और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से समय-समय पर दूध की कीमतों में बदलाव करना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में डेयरी इंडस्ट्री पर इनपुट कॉस्ट का दबाव काफी बढ़ गया है।

इससे पहले 1 मई 2025 को गुजरात और अन्य राज्यों में सभी प्रकार के अमूल दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं इससे पहले 4 जून 2024 को भी सभी वैरिएंट के दाम बढ़ाए गए थे, तब भी दाम में 2 रुपए प्रति लीटर तक की ही बढ़ोतरी की गई थी।

अमूल का मॉडल तीन लेवल पर काम करता है: डेयरी को-ऑपरेटिव सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन, स्टेट मिल्क फेडरेशन।

दूध का उत्पादन करने वाले गांव के सभी किसान डेयरी को-ऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं। ये मेंबर रिप्रजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो मिलकर डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन को मैनेज करते हैं।

तमिलनाडु विधानसभा में विजय ने जीता विश्वास मत

चेन्नई। बुधवार को सी. जोसेफ विजय ने तमिलनाडु विधानसभा में अपना बहुमत सफलतापूर्वक साबित कर दिया, जिससे तमिलगा वेत्री कजगम (टीवीके) के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार को स्थिति और मजबूत हो गई। विश्वास मत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वामपंथी दलों और विदुथलाई चिरुथाइगल काची (वीसीके) सहित गठबंधन के सभी सहयोगियों का समर्थन मिला, जिन्होंने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करते समय विजय का समर्थन किया था। हालांकि, द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम (डीएमके) ने विधानसभा से वॉकआउट करने का फैसला किया। विजय ने 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया, जिसमें 144 विधायकों ने उनकी सरकार का समर्थन किया और उन्हें आसानी से बहुमत का आंकड़ा 118 पार कर लिया। डीएमके और डीएमडीके के विधायकों ने सहन परीक्षण के दौरान वॉकआउट किया। जबकि पीएमके के चार विधायकों और भाजपा के एक विधायक ने मतदान से परहेज किया।

एन रंगासामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ

पुडुचेरी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (एआईएनआरसी) के नेता एन रंगासामी ने बुधवार को पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नर्बोन की उपस्थिति में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस समारोह के दौरान भाजपा नेता ए. नमस्सिवयम ने भी पुडुचेरी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद मुख्यमंत्री रंगासामी ने मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया और नवगठित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जन कल्याण के लिए सभी आवश्यक योजनाओं को और भी प्रभावी ढंग से लागू करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। हम निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को उत्कृष्टता के साथ निभाएंगे। उन्होंने यह भी कहा, हम अपने पुडुचेरी को शायद सिंगापुर की तरह विकसित करने जा रहे हैं।

भवानीपुर से विधायक बने शुभेंद्रु, नंदीग्राम सीट छोड़ी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बुधवार को ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला, जब राज्य विधानसभा में भव्य शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कई नवनिर्वाचित विधायकों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान संविधान निर्माता डॉ.



भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और विधायकों को औपचारिक रूप से गाई आँफ ऑनर भी प्रदान किया गया। प्रोटेम स्पीकर तापस राय की मौजूदगी में सभी विधायकों ने शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी की। इस अवसर पर भवानीपुर और नंदीग्राम विधानसभा सीट से विजयी हुए भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्रु अधिकारी ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद यह स्पष्ट हुआ कि शुभेंद्रु अधिकारी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से विधायक बने रहने का निर्णय लिया है, जबकि नंदीग्राम सीट को उन्होंने छोड़ने का फैसला किया है। इस निर्णय के साथ ही राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं।

पवन खेड़ा से गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने की पूछताछ

गुवाहाटी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा बुधवार को असम के गुवाहाटी स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज कराए गए मामले में पूछताछ का सामना किया। अधिकारियों के मुताबिक, खेड़ा जांच में सहयोग करने के लिए दिन में क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचे और अधिकारियों के सवालों के जवाब दिए।



क्राइम ब्रांच कार्यालय के बाहर मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में पवन खेड़ा ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वह कानून का पालन करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मामले में अग्रिम जमानत देते हुए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी, लेकिन साथ ही जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया था। यह मामला उस शिकायत से जुड़ा है, जो रिनिकी भुइयां सरमा ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं लगाई गई हैं। इनमें चुनाव से जुड़े मामलों में झूठे बयान देना, धोखाधड़ी, मूल्यवान दस्तावेजों की जालसाजी, सरकारी रिकॉर्ड में फर्जीबाड़ी, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल, जानबूझकर अपमान और मानहानि जैसी धाराएं शामिल हैं।

असम की सुरक्षा और विकास के लिए हम प्रतिबद्ध : हिमंत

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने भरना दिलाया कि भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में किए गए हर वादे को पूरी निष्ठा के साथ निभाया जाएगा। लगातार दूसरी बार



मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले आधिकारिक कार्यक्रम में सरमा ने अपने चार कैबिनेट सहयोगियों के साथ असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरोदोलोई के स्मारक का दौरा किया। वहां उन्होंने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सरमा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार ने औपचारिक कामकाज शुरू करने से पहले भारत रत्न गोपीनाथ बोरोदोलोई का आशीर्वाद लिया है ताकि असम की प्रगति के लिए निरंतर काम किया जा सके। उन्होंने याद दिलाया कि बोरोदोलोई ने आजादी से पहले और बाद में असम और असमिया लोगों की रक्षा के लिए कठिन परिश्रम किया था। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि असम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का उनका सपना जरूर पूरा होगा।

नया भारत और बदलती सियासी समझ

देश का मिजाज अब संकीर्णता सहन नहीं करता

एस प्रसन्नराजन

राजनीति में अक्सर तबाही के बीच स्थिरता देखने को नहीं मिलती। ऐसा तब होता है, जब लोकतंत्र अपनी तमाम हिचकिचाहटों को त्यागकर जनभावनाओं के वार की सभी बाधाओं को तोड़ने की अनुमति दे देता है। ऐसा तब होता है, जब सांस्कृतिक स्मृतियों को वे लोग सहेजते हैं, जो आने वाले कल की नब्ब को बेहतर ढंग से पहचानते हैं। यह विशेषाधिकार के दंभ में जकड़ी जड़ मानसिकता पर कल्पना की जीत है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद का भारत, भ्रमित लोगों के बिखराव को समेट रहा है; और देश का मिजाज अब राजनीति

में किसी बुरे विचार के बने रहने को बर्दाश्त नहीं करता। उप-राष्ट्रवादी दिखावे, मुक्तिदाता के रूप में कमजोर महिला का मिथक, और सर्वोच्च नेता की पूजा के बुरे विचार। जब बदनाम लोगों का पतन होता है, तो इसकी संभावना कम ही होती है कि कोई उनके प्रतीकों को याद करेगा; क्योंकि कूड़े के ढेर से हमें जो संदेश मिलता है, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते—वह यह है कि सत्ता तब सजा बन जाती है, जब उसका इस्तेमाल भ्रम में जीने वाले छोटे-मोटे सत्ताधीशों द्वारा किया जाता है। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक, नए की उम्मीद और

पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था ढह गई है। तमिलनाडु में एक नई चमक बिखरी है—एक ऐसी जगह, जहां गहरे चश्मे और रोएंद्रार टोपी वाले नायक (एमजीआर) की गाथा ने मुक्ति की राजनीति को अपने चरम पर पहुंचा दिया था। तमिल राजनीति एक ऐसे मंच की तरह बनी रही, जहां आम इन्सान का अस्तित्व ही मिट गया था; और एमजीआर के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा। भावनात्मक अतिरेक से निर्मित यह मंच ऐसे नेताओं का घर था, जो अपने लोकतांत्रिक कद से कहीं अधिक विशाल थे, जिनकी छवि गैर-राजनीतिक जुड़ावों के कारण और भी



बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई थी। यह नया रूप पुराने मिथक का एक पीढ़ीगत अपडेट है और युवाओं का आज के जमाने वाला अधीर स्वभाव, तमिल राजनीति की उस पुरानी खासियत में

समकालीन रंग भर देता है। विजय, असल में, पुरानी प्रवृत्ति की ही नई अभिव्यक्ति है। ठीक बंगल (केरल) में, पुराने को नकारना तय था। सत्ता में रहे भारतीय कम्युनिम के आखिरी नेता में सोवियत जमाने के उस उदास महाशक्तिव की झलक थी; और, अपने कार्यकाल के आखिरी पलों में लोगों के सामने खुद के इत्सान दिखाने की उस बनावटी नोटों की छोड़कर, उन्होंने यादातर एक कॉमिक-बुक के सम्राट जैसा बर्ताव किया—यह भूलकर कि उनका राज एक छोटे-से राय पर था, जिसका उस हर सत्ताधारी से बड़ा पंगा रहता था, जो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की

हिम्मत करता था। और यह भूलते हुए कि वह एक अछे प्रशासक थे, जिनके लिए तीसरा कार्यकाल संभव था। चरित्र की एक कमी ने उनसे सत्ता छीन ली और भारतीय कम्युनिम से उसका आखिरी नारा भी। पिनाराई विजयन के उत्तराधिकारी नई व्यवस्था के मालिक होने का दावा नहीं कर सकते; वे वहां इसलिए हैं, क्योंकि केरल में जो कुछ हुआ, वह कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत से कहीं यादा विजयन की करारी हार थी, और इस गठबंधन में हर तरह के सांप्रदायिकावादी तत्व शामिल हैं। अगर वामपंथ एक चिड़चिड़े बुजुर्ग के कारण कमजोर पड़ गया, तो उम्मीद है कि कांग्रेस अब लेन-देन और तुष्टीकरण की राजनीति शुरू

करेगी। केरल में आए इस बदलाव में कुछ भी नया नहीं है। आज बंगाल भारतीय राजनीति की सबसे नई कहानी बयां कर रहा है। बंगाल की स्वाभाविक राजनीतिक प्रवृत्ति में एक हिंदू तत्व निहित है। भाजपा जिस तरह से दबो हुई सांस्कृतिक स्मृति को राजनीतिक पूंजी में बदलने में सफल रही, उसका श्रेय उसके चुनाव प्रचार के स्वरूप को जाता है। बंगाल की हिंदू विरासत को पुनः स्थापित करना उसके लिए उतना ही जरूरी था, जितना कि ममता की तानाशाही को नकारना। जिस अभियान ने भाजपा को चुनाव जिताया, वह ममता पर हमले से कहीं अधिक, बंगाल की भावना के बारे में एक संवाद था।

सेंट्रल नोडल अधिकारी ने पीएमश्री स्कूलों की समीक्षा बैठक लेकर दिए आवश्यक निर्देश

■ कैरियर काउंसलिंग, ड्रॉप आउट रोकने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष जोर



पीएम श्री स्कूल भारत सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी योजना है। यह बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल निर्धारित पैरामीटर के अनुरूप कार्य करें तथा प्रत्येक मानक को गंभीरता से लागू किया जाए। उन्होंने विद्यालयों में कैरियर काउंसलिंग एवं मेंटल हेल्थ पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। विद्यार्थियों को उनके भविष्य, रोजगार एवं उच्च शिक्षा

के संबंध में उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए ताकि वे अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकें। साथ ही बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक एवं सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने पर जोर दिया गया। बैठक में ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। सेंट्रल नोडल अधिकारी ने निर्देशित किया कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न हो। यदि किसी कारणवश

विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ने के प्रयास किए जाएं तथा आवश्यकतानुसार उन्हें व्यावसायिक एवं ऑकेशनल ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विद्यालयों में नवाचार आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू की जाए। सभी स्कूलों में योग गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर लैब की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी कम्प्यूटर चालू हालत में हों तथा प्रयोगशालाएं उच्च गुणवत्ता एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त हों।

विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश भी दिए गए।

सेंट्रल नोडल अधिकारी ने कहा कि जिले में संचालित सभी 12 पीएम श्री स्कूलों का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए ताकि विद्यार्थी अपने विद्यालय पर गौरव महसूस कर सकें। उन्होंने अधिकारियों एवं शिक्षकों से पूरी प्रतिबद्धता एवं मन लगाकर कार्य करने कहा। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री बी.एल. देवांगन, जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा श्री रेखराज शर्मा एवं शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

बालोद में एनएसयूआई ने किया प्रोटेस्ट



बालोद। मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET-UG 2026) में हुई कथित अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर देशभर में आक्रोश है। इसी कड़ई में बालोद जिला मुख्यालय में NSUI ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्र नेता देवेन्द्र साहू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पदाधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की ज्ञापन सौंपते हुए

छात्र नेता देवेन्द्र साहू ने कहा कि प्रतिवर्ष देश के लगभग 22 लाख छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर दिन-रात मेहनत करते हैं। अभिभावक अपनी गाढ़ी कमाई बच्चों के भविष्य के लिए इन परीक्षाओं की तैयारी में लगा देते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाओं ने उनके भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। छात्र नेता साहू ने कहा, बार-बार राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में संधमारी होना देश की शिक्षा और चिकित्सा प्रणाली की साख गहरा प्रहार है। पूरे परीक्षा घोटाले

की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में की जाए। NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) के शीर्ष अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उन पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो। दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित हो और छात्रों पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक बोझ न डाला जाए। अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे छात्रों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए जल्द से जल्द ठोस निर्णय लिया जाए।

छात्र नेताओं का कहना है कि मामला अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया गया है, लेकिन छात्र समुदाय तब तक संतुष्ट नहीं होगा, जब तक कि पूरी प्रणाली पर गंभीरता सुनिश्चित नहीं हो जाती।

सिलेंडर ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, चंद मिनटों में चली गई चार जिंदगियां



दुर्ग। कुम्हारी में हुए आगजनी कांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जिसमें बिजली के खंभे में पहले शॉट सर्किट से चिंगारी निकली फिर कुछ सेकेंड बाद घर में रखे गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में घर पर मौजूद 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। कुम्हारी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 खदान पारा के एक घर के पास बिजली का खंबा है इस खंभे से मंगलवार को चिंगारी निकली और घर के छत पर गिरी देखते ही देखते छत के ऊपरी हिस्से में धुंआ निकलता दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद धुएं ने आग की शक्ल ली और लपेट उठती देखी तो बुझाने की कोशिश शुरु की।

सिलेंडर में धमाका होने के बाद पूरा घर तेज आग की लपटों से घिर गया। इस दिल दहला देने वाले हादसे में घर पर मौजूद चार

लोगों की मौत हो गई इसमें अनिल वैष्णव, लक्ष्मी वैष्णव, चांदनी वैष्णव और डेढ़ साल की बच्ची गोपिका वैष्णव भी शामिल है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। वहीं 4 लोगों की मौत की जानकारी लगने पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, दुर्ग सांसद विजय बघेल, विधायक, कलेक्टर और एसएसपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने मृतक के परिवारों को सलाकात कर मृतक परिवार को प्रत्येक सदस्य को 9-9 लाख देने की घोषणा की। वहीं घटना की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मृतक के परिवारों से मुलाकात कर कहा कि मुख्यमंत्री के विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण 4 लोगों की जिन्दा जलकर मौत हो गई।

जल संसाधन विभाग के ईई का ऑडियो वायरल, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

जांजगीर चांपा। मंगलवार शाम एक ऑडियो जिले में तेजी से वायरल हुआ। ऑडियो सिंचाई विभाग के एक्सक्यूटिव इंजीनियर शशांक सिंह और विभाग के ड्राइवर के बीच का बताया जा रहा है। जिसमें कथित रूप से ईई, ड्राइवर के साथ गाली गलौज कर रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया



है। अकलतरा एसडीएम के पास वाहन चालक नहीं होने के कारण उन्होंने कलेक्टर से ड्राइवर की मांग की। जिस पर एरिगेशन विभाग ने शशि कुमार साहू को

सखरू के चालक के रूप में भेजा। जिसके बाद से शशि कुमार एसडीएम की ही गाड़ी चलाने लगा। कुछ समय बाद एरिगेशन के ईई ने ड्राइवर को फिर से विभाग में लौटने को कहा, जिस पर ड्राइवर ने एसडीएम द्वारा रिलीव नहीं करने की जानकारी विभाग को दी। इस बात से नाराज

ईई शशांक सिंह ने ड्राइवर का पांच माह का वेतन रोक दिया। ड्राइवर ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की और मदद की गुहार लगाई। कलेक्टर के आदेश के बाद भी ईई ने एक माह का भुगतान किया और चार माह का वेतन भी रोक दिया, साथ ही फोन कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया।

इस घटना के बाद वाहन चालक शशि कुमार साहू ने अपने साथ ईई शशांक सिंह द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और गाली गलौज की जानकारी संगठन में दी। जिसके बाद कर्मचारी अधिकारी भवन में बैठक हुई। इस मामले में दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और आगामी रणनीति पर चर्चा

की गई। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता शशांक सिंह का कथित ऑडियो कलेक्टर के पास भी पहुंचा, जिसे कलेक्टर ने गंभीरता से लिया और मामले में अपर कलेक्टर को जांच के आदेश दिए। कलेक्टर ने दोषी अधिकारी पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया।

जंगल के अंदर जमा था ताश पत्ती का रंग, 9 जुआरियों से नकदी समेत वाहन जब्त

नारायणपुर। नारायणपुर जिले में अवैध जुआ और असाમાजिक गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कुकड़ाझोर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बोरण्ड-करमरी मुख्य मार्ग के पास जंगल में दबिष्टा देकर 9 आरोपियों को 52 पत्ती ताश के जरिए जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1 लाख 16 हजार 300 नकद, ताश पत्ती, मोटरसाइकिल और अन्य सामग्री जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक रॉबिंसन गुड्डिया के निर्देशन में जिलेभर में अवैध जुआ, सट्टा और अपराधों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत दिनांक 12 मई 2026 को थाना कुकड़ाझोर पुलिस को मुखर्षा से सूचना मिली कि बोरण्ड करमरी मुख्य मार्ग के बायीं ओर स्थित जंगल मैदान में कुछ लोग रुपए पैसे का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना कुकड़ाझोर एवं साइबर सेल नारायणपुर की संयुक्त टीम ने मौके पर घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की। पुलिस टीम को देखकर जुआ खेल रहे लोगों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 9 आरोपियों को मौके से पकड़ लिया। पुलिस ने जिन



आरोपियों को गिरफ्तार किया है उन आरोपियों में मुकेश उर्फ बिट्टू गुप्ता, प्रफुल बड़रिया, विष्णु नंदी, ऋषिकेश जायसवाल, गणेश शील, यश कुमार जैन, नरेंद्र कुलदीप, चमन कौड़ो और दीपक कतलाम शामिल हैं। सभी आरोपी नारायणपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 1 लाख 16 हजार 300 नकद राशि, 52 पत्ती ताश की 4 गुड्डियां, 3 प्लास्टिक तिरपाल, 9 मोटरसाइकिल और 2 वाहन जब्त किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। नारायणपुर पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में अवैध जुआ और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

आधी रात छत के रास्ते घर में घुसे चोर 8 सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात



डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ शहर के बीचोबीच स्थित बुधवारी पारा इलाके में आधी रात चोरों की गतिविधियों ने लोगों की नींद उड़ा दी है। वार्ड क्रमांक 15 स्थित डॉ। सचदेव गली में हुई इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक, बुधवारी पारा निवासी दिनेश कुमार साहू के घर में देर रात दो अज्ञात चोर छत के रास्ते घुस आए। पूरी घटना इलाके में लगे अलग-अलग सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। इस मामले में अब तक आठ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिनमें दोनों संदिग्ध बदमाश बेखौफ अंदाज में गली और मकान के आसपास घूमते तथा छत के रास्ते घर में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज देखने के

बाद इलाके के लोग दंग रह गए। सबसे बड़ी बात यह है कि बुधवारी पारा डोंगरगढ़ शहर के बीचोंबीच स्थित सघन आबादी वाला इलाका है, जहां देर रात तक लोगों की आवाजाही बनी रहती है। इसके बावजूद चोरों का बिना किसी डर के घंटों इलाके में घूमना और मकान में घुस जाना शहर की सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि

शहर में लगातार संदिग्ध गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस की रात गश्त का असर नजर नहीं आ रहा। लोगों ने सवाल उठाया है कि जब शहर के सबसे व्यस्त और आबादी वाले इलाके सुरक्षित नहीं हैं, तो बाहरी क्षेत्रों की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अब रात में घरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। डोंगरगढ़ एसडीओपी केसरीनंदन नायक ने बताया कि छष्टझुड़ा फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

अब महुआ नहीं, बांस, तेंदु बने गजराज की पहली पसंद

धमतरी। जंगलों में विचरण करने वाले गजराज आखिर सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? इस सवाल का दिलचस्प जवाब अब 'हाथी अलर्ट ऐप' के डेटा से सामने आया है। आम धारणा के विपरीत हाथियों की पहली पसंद महुआ नहीं रही, बल्कि वे अब बांस करील, तेंदु और साल की जड़-पत्तियों की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हाथियों की गतिविधियों की निगरानी और ग्रामीणों को सतर्क करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 'हाथी अलर्ट ऐप' ने हाथियों के खान-पान को लेकर कई अहम जानकारीयां उजागर की हैं। ऐप से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण में पता चला है कि हाथी जंगलों में बेहद विविध प्रकार का भोजन कर रहे हैं और मौसम व उपलब्धता के अनुसार अपनी पसंद भी बदल रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक हाथियों ने सबसे ज्यादा 1175 बार अन्य वनस्पतियों का सेवन किया, लेकिन यदि विशेष प्रजातियों की बात करें तो तेंदु की जड़ और पत्तियां हाथियों की सबसे पसंदीदा खाद्य सामग्री बनकर उभरी हैं, जिसे 430 बार खाते हुए दर्ज किया गया।

होर्डिंग्स लगाने के लिए एसडीएम की अनुमति जरूरी
जीपीएम। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के तहत जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद चुनावी प्रचार सामग्री के नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने होर्डिंग्स लगाने की अनुमति संबंधी आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार निर्वाचन अवधि के दौरान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स लगाने हेतु अर्थाथियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर नियमानुसार अनुमति देने के लिए संबंधित ग्रामीण क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है। आदेश में कहा गया है कि होर्डिंग्स लगाने की अनुमति संबंधित जनपद पंचायत के प्रभारी अधिकारी के समन्वय से जारी की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी अनुमति निर्वाचन आयोग एवं आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप ही प्रदान की जाएगी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रचार सामग्री के उपयोग पर सतत निगरानी रखी जाएगी।

नल से पानी नहीं लेकिन टैक्स वसूल रही नगर पालिका
खैरागढ़। खैरागढ़ जिला मुख्यालय का वार्ड क्रमांक 1 परिषदा इन दिनों सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की गहरी खाई की तस्वीर बन चुका है। यहां नगर पालिका ने वर्षों पहले नल-जल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछा दी, घरों में नल कनेक्शन भी दे दिए और पानी टैक्स की वसूली भी लगातार जारी है, लेकिन विडंबना यह है कि इन नलों से आज तक लोगों को पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हुई। वार्ड की गली में हर सुबह लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि आज पीने का पानी कहाँ से आएगा। कोई निजी टैंकर बुला रहा है, कोई दूर के बोरिंग से बाल्टियों में पानी ढो रहा है, तो कोई दूसरे मोहल्लों में जाकर पानी मांगने को मजबूर है। स्थानीय निवासी शबाना बेगम बताती हैं कि उनके मोहल्ले में वर्षों पहले पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन उसमें कभी पानी नहीं आया। पिछले सात-आठ सालों से उनका परिवार अपने खर्च पर टैंकर मंगवाकर पानी पी रहा है। उनका कहना है कि कई बार पाषंड और नगर पालिका से शिकायत की गई।

देर रात बंदूक की नोक पर ऑटो चालक से लूटपाट
अंबिकापुर। अंबिकापुर शहर से लगे कल्याणपुर जंगल क्षेत्र में मंगलवार देर रात लूटपाट की घटना सामने आई है। नकाबपोश युवकों ने राहगीरों को निशाना बनाया। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक ऑटो चालक से मोबाइल फोन लूट लिया। इसी दौरान एक कार सवार परिवार लूट की कोशिश से बाल-बाल बच गया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कल्याणपुर निवासी धर्मेन्द्र यादव मंगलवार देर रात एक शादी समारोह से अकेले लौट रहे थे। कल्याणपुर जंगल के पास पहले से घात लगाए बैठे नकाबपोश युवकों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने बंदूक दिखाकर धमकाया और उनका मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। अनापक हुई इस घटना से ऑटो चालक घबरा गया। उसने किसी तरह गांव पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी। इसी मांसे से धर्मपुर निवासी सुरेंद्र प्रसाद जायसवाल भी अपने परिवार के साथ ऑटो कार से गुजर रहे थे। बदमाशों ने उनकी कार को भी रोकने का प्रयास किया।

जीपीएम जिले से 49 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना
गोरेला पेंड्रा मरवाही। सरकार की महत्वाकांक्षी 'श्रीराम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना' के अंतर्गत आज जिले से 49 तीर्थयात्रियों को अयोध्या धाम दर्शन के लिए रवाना किया गया। श्रद्धालुओं को कलेक्ट्रेट परिसर से बस द्वारा बिलासपुर रेलवे स्टेशन के लिए भेजा गया, जहां से वे ट्रेन के माध्यम से अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री मुकेश रावटे एवं जिला पंचायत सदस्य श्री पवन पैकरा ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धालुओं को मिठाई खिलाकर शुभ यात्रा की कामना की। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं में योजना को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। मरवाही विकासखंड के ग्राम पंचायत सिलपहरी निवासी श्री सुरजपंत ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साहू जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क अयोध्या यात्रा कराना श्रद्धालुओं के लिए एक सराहनीय पहल है।

पलारी नगर पंचायत में पहली बार चुनाव, दोनों पार्टियों ने कसी कमर

बालोद। बालोद जिले में दो नगर पालिका और 6 नगर पंचायत के बाद 7वें नगर पंचायत के रूप में पलारी अस्तित्व में आया है। यहां पर पहली बार नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहा है। जिसकी घोषणा निर्वाचन विभाग ने कर दिया है, प्रशासनिक तैयारियों के बाद अब राजनैतिक दलों ने भी कमर कस ली है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दल ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। बीजेपी अभी प्रत्याशी को लेकर गुप्त सर्वे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने वार्ड के हिसाब से बैठक लेकर नामों पर चर्चा कर रही है। दोनों पार्टियां जल्द ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती



है। यहां आगामी एक जून को मतदान आयोजित होगा। इसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि पलारी नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित किया गया है, जहां करीब 3800 से 3877 मतदाता पहली बार अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। वहीं कुल 15 में से 5 वार्ड महिलाओं के लिए

आरक्षित किए गए हैं। यहां मतदाता सीधे अपने मतधिकार का उपयोग करके 15 पाषंड और नगर पंचायत अध्यक्ष चुनेंगे। जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानि ने बताया कि हमारे पदाधिकारी लगातार वहां पर बैठक कर रहे हैं। वह क्षेत्र की हम वही जा रहे हैं। यहां पर तो जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। नगर पालिका परिषद,

कि हम वहां पर चुनाव जीतने में सफल रहेंगे। वार्ड बार प्रभारी की नियुक्तियां की गई हैं। उनसे प्रत्याशियों के नाम का फीडबैक भी लिया जा रहा है और प्रत्याशी की अंतिम घोषणा प्रदेश कांग्रेस कमिटी के द्वारा जारी ही कर दी जाएगी। सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पूरी मेहनत के साथ हमारे कार्यकर्ता पलारी नगर पंचायत में कांग्रेस का झंडा लहराने के लिए तत्पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख ने बताया कि हमारे कार्यकर्ता वहां पर लगातार बैठक कर रहे हैं। आज भी हम वही जा रहे हैं। यहां पर तो जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। नगर पालिका परिषद,

बालोद, दल्ली राजहरा, नगर पंचायत, अर्जुन्दा, गुंडरदेही, गुरूर, चिखलाकसा, डौंडी, डौंडी लोहार, नगर पंचायत पलारी जातिगत समीकरणों को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि यहां पर सभी वर्ग समुदाय और समाज के लोग बराबर मात्रा में रहते हैं वहीं दो जगह अनुसूचित जाति के लिए भी आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए भी सिम आरक्षित की गई है तो इस बार प्रत्याशियों का चयन करना दोनों पार्टियों के लिए काफी मुश्किल रहेगा। क्योंकि बात पंचायत के बाद सीधे यहां नगर पंचायत के रूप में अस्तित्व में आया है। काफी लंबे समय से यहां पर मांग की जा रही थी।

जिला अस्पताल के सुरक्षाकर्मों पहुंचे कलेक्टर के पास

धमतरी। धमतरी जिला अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले कर्मियों ने अब अपने ही हाकिम यांनी सिविल सर्जन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुरक्षाकर्मियों ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में आरोप है कि उनसे वाई बॉय वाला काम कराना जा रहा था, और टेंडर समाप्त होने के बाद उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है। यही नहीं उन्हें नोटिस जारी किया है, जिससे उनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल धमतरी जिला अस्पताल इन दिनों इलाज की बजाए अन्य वजहों को लेकर जिला अस्पताल में तैनात 25 सुरक्षा गार्डों ने जिला प्रशासन के पास पहुंचकर सिविल सर्जन के खिलाफ गंभीर शिकायत

आरोप है सिविल सर्जन करवाते हैं वाई बॉय का काम
कहना है कि जो काम वार्ड बॉय और मेडिकल स्टॉफ का था, वह ड्रा-धमकाकर उनसे लिया गया। जब वार्ड बॉय ड्यूटी के दौरान सोते पाए गए और गार्डों ने उन्हें टोका तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। गार्डों का कहना है कि उनके स्पष्टीकरण को दरकिनार कर अब सिविल सर्जन एकतरफा कार्रवाई कर रहे हैं। कलेक्टर के पास पहुंचे सभी 25 गार्डों का आरोप है कि सिविल सर्जन अपनी मनमानी कर रहे हैं, और नियमों को ताक पर रखकर उनके करियर से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर ने गंभीरता दिखाते हुए जांच के आदेश दिए हैं।

संक्षिप्त समाचार

सुशासन तिहार 2026 में बिजली विभाग को मिला ग्रामीणों का धन्यवाद संदेश

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में आयोजित सुशासन तिहार 2026 आमजन की समस्याओं के समाधान के साथ-साथ शासन की सेवाओं के प्रति लोगों की संतुष्टि को भी सामने ला रहा है। जनसमस्या निवारण शिविरों में जहां नागरिक अपनी समस्याएं दर्ज करा रहे हैं, वहीं बेहतर कार्य करने वाले विभागों के प्रति आभार और बधाई संदेश भी प्राप्त हो रहे हैं। इसी क्रम में बगीचा विकासखंड के तहसील सत्रा अंतर्गत ग्राम कामारिमा निवासी नान राम ने सुशासन शिविर में विद्युत विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए एई संदेश प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि कामारिमा, खैरापाट, डुमरपानी सहित आसपास के गांवों में नियमित और निबांध विद्युत आपूर्ति हो रही है। नान राम ने बताया कि बिजली से संबंधित किसी भी समस्या की सूचना देने पर विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचकर विद्युत लाइन, तार और ट्रांसफार्मर की मरम्मत का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से उन्हें लगा कि विद्युत विभाग की तत्परता और समर्पण के लिए धन्यवाद देना चाहिए। जशपुर विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री विनोद कुमार पंडित ने बताया कि जिले में निबांध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभाग निरंतर प्रयासरत है। कहीं भी खराबी की सूचना मिलते ही अधिकारी और कर्मचारी मौसम की परवाह किए बिना तत्काल सुधार कार्य में जुट जाते हैं।

बैटरी चालित ट्रायसाइकिल, स्मार्ट केन एवं श्रवण यंत्र पाकर ट्रिपले हितग्राहियों के चेहरे

रायपुर। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की दिशा में समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर में सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसएएलएसए की बैठक उपरांत आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश श्री सिराजुद्दीन कुरैशी एवं अन्य माननीय न्यायाधीशगणों की गरिमापयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान 02 अस्थि बाधित दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्रायसाइकिल, 02 दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को स्मार्ट केन तथा 02 श्रवण बाधित दिव्यांगजनों को श्रवण यंत्र वितरित किए गए। सहायक उपकरण प्राप्त कर हितग्राहियों ने खुशी व्यक्त करते हुए इसे उनके दैनिक जीवन को सरल और आत्मनिर्भर बनाने वाला महत्वपूर्ण सहयोग बताया। इस अवसर पर दिव्यांगजनों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने तथा उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शासन निरंतर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित

रायपुर। बच्चों की असाधारण प्रतिभा और उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया है। महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस वर्ष नामांकन प्रक्रिया 31 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कार के लिए खेलता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, चौरा, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसी श्रेणियों में उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता दी जाएगी। विभाग ने बताया कि इच्छुक बच्चे, अभिभावक, संस्थाएं अथवा अन्य व्यक्ति योग्य बच्चों का नामांकन कर सकते हैं। स्व-नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध है। सभी आवेदन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन एवं विस्तृत जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल <https://awards.gov.in/> विजिट किया जा सकता है। राज्य शासन ने प्रदेश के प्रतिभाशाली बच्चों से अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करने की अपील की है, ताकि उनकी उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त सके।

हर्डिलेटेज ड्रामा के बाद 35 फीट ऊंचे होर्डिंग पर चढ़ी युवती को उतारा गया

रायपुर। शंकर नगर इलाके में बुधवार सुबह एक युवती सड़क किनारे लगे कुरीब 35 फीट ऊंचाई वाले बड़े होर्डिंग पर चढ़ गई और पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम करीब 40 मिनट तक उससे नीचे उतरने के लिए समझौता रही लेकिन जब वह नहीं मानी तो स्थानीय लोगों की मदद और एहतियात के तौर पर नीचे बड़ी सुरक्षा जाली बिछाकर उसे सुरक्षित उतारा गया। खम्हारडीह पुलिस फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवती आखिर होर्डिंग पर क्यों चढ़ी थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शंकर नगर स्थित खम्हारडीह थाना क्षेत्र में स्थित 35 फीट ऊंचे होर्डिंग पर एक युवती के चढ़कर उसके ऊपर बैठने की सूचना स्थानीय लोगों की मदद से मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए लंबी सीढ़ी लगाई गई। वहीं एहतियात के तौर पर नीचे बड़ी सुरक्षा जाली भी बिछाई गई। स्थिति बिगड़ने न पाए, इसके लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। 40 मिनट की काफी मशकत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। पुलिस युवती को अपने साथ थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने किया ईंधन संरक्षण और संसाधनों के संयमित उपयोग का आह्वान

■ऊर्जा संरक्षण की दिशा में उठाया गया हर कदम राष्ट्रनिर्माण में योगदान है - साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रहित में ईंधन संरक्षण एवं संसाधनों के संयमित उपयोग को लेकर किए गए आह्वान का समर्थन करते हुए कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों के इस दौर में पेट्रोल-डीजल जैसे मूल्यवान संसाधनों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करना हम सभी का राष्ट्रीय दायित्व है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इसी भावना से प्रेरित होकर राज्य शासन द्वारा शासकीय स्तर पर ईंधन की खपत कम करने और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में ठोस पहल की जा



रही है। उन्होंने कहा कि उनके आधिकारिक भ्रमणों के दौरान अब के व ल अत्यावश्यक वाहनों को ही कार्केड में शामिल किया जाएगा। साथ ही मंत्रीगणों तथा विभिन्न निगम-मंडलों के पदाधिकारियों से भी वाहनों एवं अन्य सरकारी संसाधनों के संयमित उपयोग का आग्रह किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शासकीय परिवहन व्यवस्था को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में भी कार्य करेगी। इसके तहत समस्त शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में परिवर्तित करने की दिशा में ठोस कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल ईंधन की बचत करेगा, बल्कि

भाजपा कार्यसमिति की बैठक : शाह और साय को दिया गया स्टैंडिंग ओवेशन

■महिला आरक्षण के विरोध का कांग्रेस भुगतेली खामियाजा : साव

रायपुर। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बुधवार को अहम बैठक हुई। बैठक में नक्सल उन्मूलन से लेकर देश के विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा करने के साथ महिला आरक्षण अधिनियम के लोकसभा में गिरने परपाटी पदाधिकारियों ने कांग्रेस की आलोचना की।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बैठक को लेकर कहा कि पहले बैठकों में कार्यकर्ता अपनी पीड़ा बताते थे, अब भाजपा कार्यसमिति में नक्सल उन्मूलन पर चर्चा हो रही है। बस्तर के मडई-मेलों में रंगत लौटी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया है। भाजपा ने नेतृत्व के लिए आभार जताया है। वहीं बैठक में बस्तर को लेकर



बैठक में विस्तृत आंकलन करने की जानकारी देते हुए कहा कि बस्तर बदल रहा है, विकास की नई दिशा मिल रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यसमिति की बैठक पर कहा कि भाजपा की दो दिवसीय बैठक आहूत की गई। कल प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी की बैठक हुई है, आज भाजपा कार्यसमिति की बैठक जो रही है। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ है। चुनाव में भाजपा की जीत पर जन्ता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। वहीं महिला आरक्षण के लोकसभा में गिरने पर कहा कि कांग्रेस ने विरोध किया है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को तो भुगतना पड़ेगा।

भाजपा कोर ग्रुप से बड़े नेता बाहर

बृजमोहन के साथ भाजपा कर रही सौतेला व्यवहार : दीपक बैज

रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा की नई कोर ग्रुप में दिग्गज नेताओं को बाहर करने के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने निशाना साधते हुए भाजपा में गुटबाजी चरम पर होने का आरोप लगाया है। कहा कि भाजपा बृजमोहन अग्रवाल के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस बयान पर भाजपा सांसद बृजमोहन ने पलटवार करते हुए कहा कि वह जब तक सक्रिय हैं, तब तक उन्हें कोई किनारे नहीं कर सकता।

दरअसल, मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई कोर ग्रुप की बैठक में निर्णय लेते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री रामविचार नेताम और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल को बाहर किया गया। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बृजमोहन अग्रवाल पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। भाजपा उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही हैं। भाजपा में गुटबाजी चरम पर है। एक अनुभवी नेता को नजरअंदाज करना पार्टी की गुटबाजी को उजागर करती है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दीपक

बैज के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा कोर कमेटी में रखना और निकालना बेहद ही सामान्य प्रक्रिया है। पिछले दस सालों से कोर कमेटी का हिस्सा रहा। उन्होंने कहा कि उनके साथ सौतेला व्यवहार कोई नहीं कर सकता। वह जब तक सक्रिय हैं, तब तक उन्हें कोई किनारे नहीं कर सकता।

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के काफिला कम करने और सरकारी वाहनों में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के संबंध में जल्द ही कटींग पर समीक्षा की बात पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यजनक बयान है कि समीक्षा करेगे। अब तक सरकार क्या कर रही थे। किसी तरह की क्लिन्न नहीं हैं कहने के बाद अब तक लीपापोती का काम कर रहे थे। वित्त मंत्री के अपना काफिला छोड़ने का ऐलान करने से क्या दिक्रत कम हो जाएगी।

बैज ने कहा कि सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। विश्व से भी चर्चा करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही आर्थिक संकट को लेकर आगाह किया था।

पीएम आवास निर्माण तेजी से पूरा कराने लगी जनचौपाल

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों का निर्माण समय-सीमा में पूरा कराने के लिए जिला प्रशासन बलरामपुर-रामानुजगंज ने निगरानी और समीक्षा तेज कर दी है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत बदौली में जिला पंचायत सीईओ की मौजूदगी में विशेष जनचौपाल और समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम पंचायत बदौली, कुन्दीकला और शिवपुर के प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही बड़ी संख्या में शामिल हुए। बैठक के दौरान हितग्राहियों से सीधे संवाद कर उनके आवास निर्माण की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई। जिन आवासों का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ उन्हें तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। जिन आवासों का निर्माण प्लिंथ से टॉप स्तर तक पहुंच चुका है, उनका कार्य आगामी 15 दिनों



के भीतर पूर्ण किया जाए। इसके अलावा टॉप लेवल पूरा होने के 10 दिनों के भीतर सेंटिंग और ढलाई का कार्य अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में अधिकारियों के दस्तावेज ग्राम सभा प्रस्ताव सहित आवास योजना के हितग्राहियों को समय पर तकनीकी मार्गदर्शन और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए, ताकि निर्माण कार्य में किसी

प्रदूषण नियंत्रण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों से सर्वजनिक परिवहन का अधिकाधिक उपयोग करने, कारपूलिंग अपनाने तथा अनावश्यक निजी वाहनों के उपयोग से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव लाकर हम बड़े सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यदि प्रत्येक नागरिक ईंधन बचत को अपनी जिम्मेदारी माने, तो यह अभियान एक व्यापक जन-आंदोलन का रूप ले सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ ईंधन संरक्षण को जनभागीदारी का अभियान बनाना समय पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में भी कार्य करेगी। इसके तहत समस्त शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में परिवर्तित करने की दिशा में ठोस कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल ईंधन की बचत करेगा, बल्कि

अधिकारी-कर्मचारी अनुशासित और संकल्पित होकर विकसित छत्तीसगढ़ के लिए करें काम : प्रभारी सचिव

■अवैध नशीली दवाइयों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश

रायपुर। प्रभारी सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी अनुशासित और संकल्पित होकर छत्तीसगढ़ के लिए संवेदनशीलता के साथ काम करें। उन्होंने अवैध नशीली दवाइयों पर नियंत्रण हेतु सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने नारकोटिक्स नियंत्रण एवं नशामुक्ति अभियान को जानकारी ली तथा नशामुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करने कहा।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने दुर्ग जिले में आज आयोजित नारकोटिक्स नियंत्रण एवं नशामुक्ति अभियान की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने बैठक में जिले में मादक पदार्थों की रोकथाम, नशामुक्ति केंद्रों की व्यवस्थाओं तथा संबंधित विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की भी जानकारी ली।

दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव श्री बोरा ने बैठक में नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को आपसी समन्वय बनाकर संयुक्त समिति गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को नशामुक्ति केंद्रों में तीन माह तक रखा जाता है। इस अवधि को बढ़ाने पर भी विचार करने

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने घटाया अपना काफिला

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए देशवासियों से की गई अपील का सम्मान करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने अपने प्रोटोकॉल काफिले से 4 वाहनों का उपयोग कम करने का फैसला लिया है। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि यह राष्ट्रहित में संसाधनों के संरक्षण और जिम्मेदार नागरिक कर्तव्य की भावना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम है। जब वैश्विक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, तब परिवार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसाधनों के संरक्षण का संदेश हम सभी भारतवासियों के लिए अनुकरणीय है। ऐसे समय में प्रत्येक जनप्रतिनिधि और नागरिक का दायित्व बनता है कि वह संयम, सादगी और जिम्मेदारी का परिचय दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देशवासियों को राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने की प्रेरणा दी है और उसी भावना के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। डॉ. रमन सिंह ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे वर्तमान परिस्थितियों को गंभीरता से समझें।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने छोड़ा विशेष प्रोटोकॉल और सुरक्षा काफिला

राष्ट्र प्रथम की भावना से ऊर्जा संरक्षण का संदेश

रायपुर। वैश्विक ऊर्जा संकट, बढ़ती ईंधन खपत तथा पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन संरक्षण एवं संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के आह्वान से प्रेरित होकर मंत्री श्री अग्रवाल ने अपने राजकीय दौरो के दौरान पायलट वाहन, फॉलो वाहन तथा अन्य विशेष प्रोटोकॉल का उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया है।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में ईंधन की बचत केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। इसी भावना के अनुरूप उन्होंने अपने सुरक्षा काफिले में केवल अपरिहार्य वाहनों को ही शामिल करने तथा अनावश्यक वाहनों को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सामान्य स्थिति बहाल होने तक वे किसी भी प्रकार की पायलट,



सर्वजनिक परिवहन प्रणाली, कारपूलिंग तथा संसाधनों के संयमित उपयोग को अपनाएँ, इससे न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के संतुलित उपयोग की दिशा में देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा को आत्मसात करते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि शासन और जनप्रतिनिधि स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर समाज को सकारात्मक संदेश दे सकें।

फॉलो गाड़ी अथवा विशेष प्रोटोकॉल का उपयोग नहीं करेंगे।

श्री अग्रवाल ने कहा कि यह समय जिम्मेदारी, संयम और जनभावनाओं के साथ खड़े रहने का है। राष्ट्रहित में प्रत्येक नागरिक की इसमें सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। मंत्री श्री अग्रवाल ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ



के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार पीड़ितों को पृथक-पृथक रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। नशे की लत से मुक्त हो चुके व्यक्तियों के सफलता का व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए। जिस समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचे और अन्य लोग भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित हों। इसके लिए छोटे-छोटे वीडियो एवं क्लिप्स तैयार कर जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। बैठक में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह विशेष रूप से मौजूद थे।

बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2026 में एनडीपीएस एक्ट एवं नारकोटिक्स एक्ट के तहत कुल 68 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में गांजा, गांजा पौधा, हेरोइन, नशीली दवाइयां, अफीम, अफीम के बीज तथा डोडा से संबंधित जत्ती की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 9 लाख 25 हजार रुपये है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में पीआईटी एनडीपीएस के तहत 9 प्रकरण तैयार किए गए हैं तथा 36 वाहनों की नीलामी भी कराई गई है। उन्होंने बताया कि जनवरी से अप्रैल 2026 तक स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधियों की रोकथाम को लेकर जिले में व्यापक स्तर पर कार्यवाही की गई।

खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जनवरी से अप्रैल तक की अवधि में कुल 715 स्थानों पर निरीक्षण किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 32 नोटिस जारी किए गए। वहीं नारकोटिक्स दवाइयों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलने पर 4 मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा पुलिस एवं संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त रूप से 11 कार्रवाई भी की गई हैं। प्रभारी सचिव ने कहा कि स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधियों के विक्रय एवं वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाए। साथ ही औषधियों का नियमित भौतिक सत्यापन करने तथा जहां से अवैध सप्लाई हो रही है, वहां भी सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाकर संयुक्त रूप से कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

सुशासन तिहार में मिली राहत, समाधान शिविर में बना आयुष्मान कार्ड

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आयोजित सुशासन तिहार 2026 अब लोगों के लिए सिर्फ शिकायतों के निराकरण का मंच नहीं रह गया है, बल्कि यह शासन की योजनाओं को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम भी बनता जा रहा है। गांवों में लगाए जा रहे समाधान शिविरों में लोगों को त्वरित सेवाएं मिल रही हैं और कई परिवारों को बड़ी राहत भी प्राप्त हो रही है।

ऐसी ही एक तस्वीर सकी जिले के जैजैपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत रायपुरा में आयोजित समाधान शिविर में देखने को मिली, जहां ग्राम रायपुरा निवासी श्रीमती निर्मला साहू को मौके पर ही आयुष्मान कार्ड प्रदान किया गया। शिविर में पहुंचकर उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने



तत्परता दिखाते हुए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की और अल्प समय में उनका कार्ड बनाकर उन्हें सौंप दिया। आयुष्मान कार्ड हाथ में मिलते ही निर्मला साहू के चेहरे पर संतोष और राहत साफ दिखाई दी। उन्होंने कहा कि अब बीमारी के इलाज को लेकर आर्थिक चिंता काफी हद तक कम हो गई है। इस कार्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी, जिससे जरूरत पड़ने पर बेहतर इलाज कराना संभव हो सकेगा। उन्होंने शासन और जिला प्रशासन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए किसी सहारे से कम नहीं है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह सुविधा बड़ी राहत लेकर आई है, जहां आर्थिक अभाव के कारण कई बार लोग समय पर इलाज नहीं करा पाते।

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)				
ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना				
eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in				
निम्नलिखित कार्यो के लिए दिनांक 01.06.2026, 17:30 तक ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है:-				
सिस्टम निविदा क्रमांक	निविदा सूचना क्रमांक एवं दिनांक	कार्य का नाम	निविदा की लागत जी.एस.टी. छोड़ कर (लाख में)	आमंत्रण का क्रमांक
190552	01/व. ले.लि / 2026-27 दिनांक 11.05.2026	धनुहार नाला पर अमरपुर एनीकट योजना का निर्माण कार्य।	337.47	प्रथम आमंत्रण
190555	02/व. ले.लि / 2028-27 दिनांक 11.05.2026	गन्जुपानी जलाशय योजना के बांध एवं नहर का जीर्णोद्धार कार्य।	250.39	प्रथम आमंत्रण
190556	03/व. ले.लि / 2026-27 दिनांक 11.05.2026	बदरा जलाशय योजना के बांध एवं नहर का नवीनीकरण कार्य।	340.20	प्रथम आमंत्रण
अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्यूरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 18.05.2026, समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते है।				
नोट:-1. निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित / पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।				
2. निविदा को अनुमानित लागत एस.ओ.आर. दिनांक 01.05.2025 एवं दिनांक 08.08.2025 के जारी संशोधन के अनुसार है।				
कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.) क्ते मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)				
जी-262700647 /9				

मोदी और शाह की निगाह अब पंजाब के मोर्चे पर

हरीश गुप्ता

भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब लंबे समय से वह अंतिम राजनीतिक गढ़ रहा है जिसे वह अकेले कभी जीत नहीं पाई। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक होने के कारण, नरेंद्र मोदी-अमित शाह की जोड़ी ने सीमावर्ती राज्य में राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से पैठ बनाने के लिए एक आक्रामक बहुआयामी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। भाजपा का मानना ​​है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार कमजोर होती जा रही है। अमृतसर के खासा में सेना छावनी की चारदीवारी के पास और जालंधर में बीएसएफ पंजाब फ़र्टियर मुख्यालय के बाहर हाल ही में हुए कम तीव्रता वाले विस्फोटों ने भाजपा को राष्ट्रीय सुरक्षा का एक सशक्त मुद्दा दे दिया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव की इस टिप्पणी ने कि इन घटनाओं में पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ हो सकता है, भाजपा को अपने हमले को और तेज करने का मौका दिया है। भाजपा ने मान सरकार को एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में सुरक्षा के मामले में कमजोर बताया है, जहां खालिस्तानी तत्व एक बार फिर से संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष द्वारा मान के कथित तौर पर एक आधिकारिक समारोह में नशे में पहुंचने के आरोपों ने मुख्यमंत्री की छवि को लेकर चल रही बहस को और हवा दे दी है। लेकिन भाजपा का सबसे बड़ा हथियार उसकी राजनीतिक रणनीति हो सकती है। पार्टी ने चुपचाप बाहरी नेताओं का एक मजबूत नेटवर्क खड़ा कर लिया है। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ कांग्रेस से आए थे। केंद्रीय मंत्री रजनीत सिंह बिंद्रा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले से ही भाजपा में हैं। अब राघव चड्ढा और छह आप राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने से पार्टी की विस्तार योजनाओं को नई गति मिली है। दिल्ली से मिल रहा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है- पंजाब को अब एक असंभव राज्य के रूप में नहीं देखा जा रहा है। बंगाल के बाद, भाजपा अब देश के अशांत सीमावर्ती क्षेत्र में अपनी अगली बड़ी सफलता हासिल करना चाहती है। दशकों से, भारत की विपक्षी पार्टियों ने एक राजनीतिक कला में महारत हासिल की है: जमीनी स्तर के नेताओं के बजाय वंशवाद को महत्व देना। वहीं दूसरी ओर, भाजपा ने ठीक इसके विपरीत महारत हासिल की- वंशवादी दरबारों द्वारा उपेक्षित मत्वकांक्षी क्षेत्रीय नेताओं को चुनकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। यही वह साझा सूत्र है जो शुभेंदु अधिकारी और हिमंत बिस्वा सरमा को जोड़ता है। अधिकारी मजबूत तुलामूल के एक पदाधिकारी नहीं थे। वे नंदीग्राम के सूत्रधार थे, जनआंदोलनकारी थे जिन्होंने ममता बनर्जी को एक आम कार्यकर्ता से बंगाल की निर्निर्बाद शासक बनाने में अहम भूमिका निभाई। वर्षों तक उन्हें स्वाभाविक राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता रहा। लेकिन उत्तराधिकार की कहानी तब बदल गई जब पार्टी ने अभिषेक बनर्जी की ओर रुख किया, जो उनके भतीजे थे और सत्ता के लिए तैयार थे। असम की कहानी भी कुछ हद तक मिलती-जुलती है। सरमा ने पूर्वोत्तर में कांग्रेस को 25 वर्षों तक कुड़ी मेहनत से खड़ा किया। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन की राजनीति शुरू हुई, तो सत्ता प्रतिष्ठान ने पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई का समर्थन करना अधिक उचित समझा। सरमा 2015 में भाजपा में शामिल हो गए। आज वे न केवल असम के सबसे प्रभावशाली नेता हैं, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार भी हैं। इससे सबक निमलता है कि पार्टी वंशवाद से कमजोर हो जाती है और अक्सर अपने सबसे प्रभावशाली नेताओं को खो देती है।

पुराण दिग्दर्शन

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

अर्थात् (क) जो विष्णु है वही यज्ञ है (ख) यज्ञ ही पुरुष है, हविर्धान उसका शिर है, आहवनीय उसका मुख है, सद्गू उसका उदर है (ग) यह जो दक्षिणा है सो यज्ञ की पुरोगवि अग्रगण्य है (घ) दक्षिणारहित यज्ञ विष्टष्ट हो जाता है इसीलिये कहा जाता है कि यज्ञ में अवश्य ही थोड़ी-बहुत दक्षिणा देनी चाहिये।

विवेचन

उपर्युक्त आख्यान में पुराणों की विशिष्टशैली के अनुसार श्रीवेदव्यास जीने ऐतिहासिक अंश को याज्ञिक तत्त्व के साथ विर्मिश्रित करके प्रकट किया है, तत्नुसार यहाँ यह दिखलाया गया है कि जिस प्रकार संसार में स्त्रो पुरुष की अर्धाङ्गिनी मानी जाती है और उक्त दम्पती का अनिवार्य ऐक्य ही सन्तान उत्पादन का कारण होता है, ठीक इसी प्रकार वैदिक विधान में दक्षिणादान यज्ञ का एक आवश्यक अङ्ग है

ईरानी विमानों को छिपा कर पाकिस्तान ने उतार दिया कर्ज

नीरज कुमार दुवे

1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब भारतीय हमलों से बचाने के लिए ईरान ने पाकिस्तानी सैन्य विमानों और संसाधनों को सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराया था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि पांच दशक बाद पाकिस्तान उसी एहसान का बदला चुकाता दिखाई देगा। अब आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई और क्षेत्रीय तनाव के बीच पाकिस्तान ने ईरानी विमानों को अपने सैन्य ठिकानों पर सुरक्षित शरण दी। इस तरह इस्लामाबाद ने तेहरान का पुराना कर्ज तो उतार दिया है लेकिन अब वह खुद संकट में फँसता दिखाई दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिर्रे से खारिज किया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने दुक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की जटिल कूटनीतिक राजनीति को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया है कि इस तरह के दावे वास्तविकता से परे हैं, क्योंकि नूर खान वायुसेना अड्डा राजधानी के अत्यंत व्यस्त और आबादी वाले हिस्से में स्थित है। पाकिस्तान का कहना है कि वहां किसी भी बड़े सैन्य बेड़े या विमानों को छिपाकर रखना संभव ही नहीं है। दूसरी ओर अमेरिकी प्रशासन ने भी अब तक सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान पर कोई सीधा आरोप नहीं लगाया है, जिससे स्थिति और अधिक जटिल दिखाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार ईरान ने संभावित खतरे को देखते हुए अपने कुछ नागरिक विमानों को पड़ोसी अकगानिस्तान की ओर भेजा। अफगान नागरिक उड्डयन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि महान एयर का एक विमान संघर्ष सेज होने से पहले काबुल पहुंचा था और बाद में सुरक्षा कारणों से उसे हेरात स्थानांतरित कर दिया गया। बताया गया कि अफगान क्षेत्र में पाकिस्तानी हवाई हमलों की खबरों के बाद यह आशंका पैदा हो गई थी कि काबुल हवाई अड्डा भी संभावित निशाना बन सकता है। इन घटनाओं ने दक्षिण एशिया के जानकारों को



पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया है कि इस तरह के दावे वास्तविकता से परे हैं, क्योंकि नूर खान वायुसेना अड्डा राजधानी के अत्यंत व्यस्त और आबादी वाले हिस्से में स्थित है। पाकिस्तान का कहना है कि वहां किसी भी बड़े सैन्य बेड़े या विमानों को छिपाकर रखना संभव ही नहीं है।

1971 के दौर की याद दिला दी है। उस समय शाह मोहम्मद रजा पहलवी के नेतृत्व वाला ईरान पाकिस्तान का प्रमुख समर्थक बनकर सामने आया था। तेहरान ने इस्लामाबाद को हेलिकाप्टर, ईंधन, गोला बारूद और सैन्य उपकरणों के कलपुर्जे उपलब्ध कराए थे। कई रिपोर्टों में यह भी उल्लेख मिलता है कि पाकिस्तान के कुछ सैन्य विमानों ने ईरानी वायुसेना अड्डों पर शरण ली थी।

बाद में सार्वजनिक हुए अमेरिकी दस्तावेजों से पता चला था कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन प्रशासन ने पर्दे के पीछे ईरान को पाकिस्तान की सहायता के लिए प्रोत्साहित किया था। उस दौर में अमेरिका और चीन दोनों ही पाकिस्तान को कमजोर होने से बचाना चाहते थे। शीत युद्ध के समय ईरान और पाकिस्तान दोनों सोवियत विरोधी सैन्य गठबंधन सेन्टो के सदस्य थे और निक्सन प्रशासन इन्हें क्षेत्र में सोवियत प्रभाव को रोकने वाले

ललित गर्ग

आज पूरी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां युद्ध, आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट और वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं ने मानव सभ्यता को नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया है। खाड़ी देशों में लंबे समय से चल रहे संघर्ष और युद्ध की विभीषिका ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरे तक प्रभावित किया है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखलाओं का बाधित होना, डॉलर के मुकाबले विभिन्न देशों की मुद्राओं का कमजोर होना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्पन्न मुद्दाओं ने लगभग हर राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। भारत भी इन परिस्थितियों से अछूता नहीं रह सकता।

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है और सोने का भी विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ईंधन के संयमित उपयोग और सोने ने लगभग हर राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। भारत भी इन परिस्थितियों से अछूता नहीं रह सकता। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है और सोने का भी विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ईंधन के संयमित उपयोग और सोने ने लगभग हर राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। भारत भी इन परिस्थितियों से अछूता नहीं रह सकता। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है और सोने का भी विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ईंधन के संयमित उपयोग और सोने ने लगभग हर राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। भारत भी इन परिस्थितियों से अछूता नहीं रह सकता।

भारत की संस्कृति मूलतः संयम प्रधान रही है। भारतीय जीवन-दर्शन में संयम को केवल व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। हमारे ऋषियों, मुनियों और

ज्ञान/मीमांसा

मोदी के राष्ट्रहित के आह्वान में भी राजनीति क्यों?



महापुरुषों ने सदैव आवश्यकता और विलासिता के बीच अंतर करना सिखाया। महावीर, बुद्ध, गांधी और विनोबा भावे जैसे महापुरुषों ने त्याग और संयम को ही मानवता की सबसे बड़ी शक्ति बताया। भारतीय संस्कृति कहती है कि जितना आवश्यक हो उतना ही उपभोग करो, क्योंकि असीमित उपभोग अंततः संकट को जन्म देता है। यही कारण है कि भारतीय सभ्यता हजारों वर्षों तक टिकाऊ और संतुलित बनी रही। आज जब पूरी दुनिया उपभोक्तावाद के दुष्परिणाम भुगत रही है, तब भारत की यही संयम आधारित संस्कृति समाधान का मार्ग दिखा सकती है। सोने के प्रति भारतीय समाज का आकर्षण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर गहरा रहा है। विवाह, पारिवारिक उत्सव, धार्मिक परंपराएं और सामाजिक प्रतिष्ठा में सोने का विशेष स्थान है। लेकिन यह भी एक कठोर सत्य है कि भारत का अधिकांश सोना आयातित होता है। हर वर्ष अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार सोने के आयात पर खर्च होता है। यह सोना उत्पादन या औद्योगिक विकास में उपयोग होने के बजाय घरों और लॉकरों में बंद होकर निष्क्रिय पड़ा रहता है। ऐसे समय में जब विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा हो और रुपये की कीमत लगातार गिर रही हो, तब सोने की खरीद में संयम बरतने की अपील आर्थिक दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक है। यह किसी की परंपराओं के विरोध में नहीं, बल्कि देश की आर्थिक मजबूती के पक्ष में उठाया गया कदम है।

इसी प्रकार ईंधन के उपयोग में संयम भी समय की आवश्यकता है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयातित तेल पर निर्भर है। खाड़ी देशों में युद्ध और अस्थिरता के कारण तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका सीधा प्रभाव पेट्रोल, डीजल, परिवहन, उद्योग और मंहंगई पर पड़ता है। यदि

नागरिक ईंधन के अनावश्यक उपयोग को सीमित करें, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, ऊर्जा बचत को जीवनशैली का हिस्सा बनाएं, तो इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। संयम का अर्थ केवल त्याग नहीं होता, बल्कि दूरदर्शिता और जिम्मेदारी भी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील इसी जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित प्रतीत होती है। उन्होंने किसी प्रकार की जबर्दस्ती या प्रतिबंध की बात नहीं की, बल्कि नागरिकों से स्वैच्छिक सहयोग की अपेक्षा की। यह लोकतांत्रिक नेतृत्व की पहचान है।

एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री का कर्तव्य केवल संकट आने पर कदम उठाना नहीं होता, बल्कि संकट के संकेतों को पहचानकर समय रहते जनता को तैयार करना भी होता है। आज जब दुनिया के कई देशों में आर्थिक अस्थिरता के कारण भारी महंगई, बेरोजगारी और सामाजिक तनाव देखने को मिल रहे हैं, तब भारत अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति में है। यह केवल संयोग नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में अपनाई गई आर्थिक नीतियों, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर भारत अभियान और वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत स्थिति का परिणाम है। यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वव्यापी संकटों के बावजूद भारत ने अपने नागरिकों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया। महामारी से लेकर युद्धजनित परिस्थितियों तक भारत सरकार ने लगातार राहत योजनाएं चलाई, गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया, किसानों और मध्यम वर्ग को विभिन्न प्रकार की सहायता दी तथा अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाए। वैश्विक मंदी और युद्ध के वातावरण में भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल बना हुआ है। यह प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता का प्रमाण है।

दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि देशहित के ऐसे विषयों पर भी कुछ राजनीतिक दल संकीर्ण राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे। लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार सभी को है, लेकिन हर विषय को राजनीतिक लابی-हानि के तराजू में तौलना

राष्ट्रहित के विरुद्ध है। यदि प्रधानमंत्री जनता से संयम की अपील करते हैं तो विपक्ष को चाहिए कि वह भी जनता को जागरूक करें, न कि भय और भ्रम का वातावरण बनाए। राजनीति तब तक स्वस्थ मानी जाती है जब तक वह राष्ट्रहित से जुड़ी रहे। लेकिन जब राजनीति केवल विरोध के लिए विरोध करने लगे और राष्ट्रीय संकटों को भी अवसर की तरह देखने लगे, तब वह लोकतंत्र को कमजोर करती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरा देश एक परिवार की तरह सोचते हुए राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माने। संकट के समय संयम, अनुशासन और सहयोग ही किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। भारत ने इतिहास में अनेक बार यह सिद्ध किया है कि जब भी राष्ट्र पर संकट आया, भारतीय समाज ने अद्भुत त्याग और एकता का परिचय दिया। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर युद्धकाल तक, भारतीय जनता ने अपने निजी हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को महत्व दिया है। आज फिर वही समय है जब हमें समझना होगा कि अनावश्यक उपभोग, दिखावे की प्रवृत्ति और अंधाधुंध विलासिता अंततः देश की आर्थिक मजबूती को कमजोर करती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को इसी व्यापक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। यह केवल सोना न खरीदने या ईंधन बचाने का संदेश नहीं, बल्कि आत्मसंयम, आत्मअनुशासन और राष्ट्रीय जिम्मेदारी का संदेश है। भारतीय संस्कृति का मूल स्वर भी यही रहा है कि व्यक्ति अपने आचरण से समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाए। यदि हम संयम को जीवन का हिस्सा बना लें तो अनेक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान स्वतः संभव हो सकता है। आज दुनिया जिस अनिश्चितता और संकट के दौर से गुजर रही है, उसमें भारत अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में खड़ा है। इसका श्रेय देश जनता की सामर्थ्य के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भी जाता है। ऐसे समय में आवश्यकता राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सकारात्मक सोच की है। संयम केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि राष्ट्रनिर्माण का आधार है। यदि हम इस भावना को समझ सकें, तो न केवल वर्तमान संकटों का सामना कर पाएंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकेंगे।

संभाजी महाराज



सोयराबाई ने उनके राजनीतिक जीवन में कई बार दखल किया। संभाजी को संस्कृत, मराठी, फारसी और हिंदी भाषा में दक्षता हासिल थी। वह एक विद्वान होने के साथ लेखक भी थे। संभाजी महाराज बहादुर होने के साथ चतुर राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने राजनीतिक बारिकियों को बहुत अच्छे से आत्मसात किया था। महज 9 साल की उम्र में शिवाजी महाराज उनको अपने साथ यात्रा पर ले गए। संभाजी की सोच थी कि अगर वह छोटी उम्र में मुगल दरबार की घटनाओं और राजनीति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो यह भविष्य महाराज की देखभाल उनकी दादी राजमाता जीजाबाई ने की थी। हालांकि उनकी सौतेली मां पुतलीबाई भी उनसे स्नेह रखती थीं। लेकिन संभाजी की सौतेली मां

फलों की टोकरी में छिपकर वहां से भाग निकले। संभाजी का भी सपना था कि वह अपने पिता शिवाजी की तरह महान बने। शिवाजी की मौत के बाद संभाजी ने उनसे एक कदम आगे निकलने की ठान ली। इसी कड़ी में उसने 15 वर्षों तक औरंगजेब की विशाल सेना से युद्ध किया। संभाजी के नेतृत्व में मुगल सेना कई बार पीछे हटने को मजबूर हुई। हालांकि 1689 में औरंगजेब की सेना ने संभाजी को पकड़ लिया और उनसे इस्लाम धर्म कुबूल करने का आदेश दिया, लेकिन संभाजी महाराज ने धर्म परिवर्तन करने से इंकार कर दिया। जिस पर औरंगजेब की तरफ से उनको तरह-तरह की यातनाएं दी गईं। वहीं 11 मार्च 1689 को संभाजी के सिर को कलम कर दिया गया।

आज का इतिहास

- 1796 अंग्रेजी चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के खिलाफ एवासीन के रूप में काउपॉक्स का परीक्षण शुरू किया।
- 1800 द्वितीय गठबंधन: जनरल ल्यूयस-एलेक्जेंडर बर्थियर के तहत फ्रांसीसी सेनाएं ओस्ट्रा घाटी में फोर्ट बर्ड में 400 ऑस्ट्रो-पिदममोन सैनिकों द्वारा रोकी गई।
- 1811 पराग्वे स्पेन की पराधीनता से मुक्त हुआ।
- 1868 टोकुगावा के बोशिन बार-टूप्स ने उंडुनोमिया कैसल के ब्रेट से हटा दिया और उत्तर की ओर पीछे हटकर निको और आइजू की ओर बढ़ गए।
- 1870 नेक्सन फुटबॉल क्लब और नेल्सन कॉलेज के बीच न्यूजीलैंड में पहला रग्बी मैच खेला गया।
- 1908 पहली बार किसी व्यक्ति ने हवाई जहाज में उड़ान भरी।
- 1912 चीन ने छह बिजली रेल ऋष समझौते को मना किया।
- 1914 बुद्धो विल्सन ने मातृ दिवस की घोषणा पर हस्ताक्षर किए।
- 1925 श्रीमती डोलाय, अंग्रेजी के सबसे आधुनिक उपन्यासों में से एक, नवीनतम वर्जीनिया वूल्फ, प्रकाशित हुई थी।
- 1939 लीना मदीना पांच साल, सात महीने और सत्रह दिन की उम्र में सबसे कम उम्र की पक्षी माँ बनी, जब उसने 14 मई 1939 को एक सीज़ेरियन सेक्शन से एक लड़के को जन्म दिया।
- 1940 द्वितीय विश्व युद्ध-डच सेनाओं के थोक ने नीदरलैंड की लड़ाई को समाप्त करते हुए, वेहरमाच के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
- 1941 36,000 परशियन यहूदी को गिरफ्तार किया गया।
- 1943 द्वितीय विश्व युद्ध: क्राॅंसलैंड के तट पर एक जापानी पनडुब्बी हिरा ओस्ट्रेलियाई अस्पताल रिप सेंटर पर हमला किया गया और डूब गया, जिसमें 268 लोग मारे गए।
- 1948 डेविड बेन-गुरियन ने सार्वजनिक रूप से तेल अवीव में वर्तमान में स्वतंत्रता हॉल में इज़राइली घोषणा की आधिकारिक तौर पर पढ़ा, आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन के पूर्वा्रब्रिटिश जनादेश के कुछ हिस्सों में एक नए यहूदी राज्य की स्थापना की।
- 1948 इज़राइल ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की।
- 1951 वेल्स में टैलीलिन रेलवे दुनिया का पहला रेलवे बन गया, जिसे स्वयंसेवकों द्वारा संरक्षित किया गया, जब इसे 14 मई, 1951 को व्हार्फ और रिहाइज़ेशन स्टेशनों के बीच चलने वाली ट्रेनों के साथ फिर से खोला गया।
- 1961 एनिस्टन, अलबामा, अमेरिका में, कू क्लक्स क्लैनमेन की भीड़ ने फ्रीडम राइडर्स को बसों पर हमला किया, जो स्थानीय अलबामा कानूनों को चुनौती देने के लिए मिश्रित नस्लीय समूहों में अंतरराज्यीय बसों की सवारी कर रहे थे।

वैश्विक संकट के बीच सबसे बड़े कूटनीतिक मिशन पर निकल रहे हैं मोदी

नौरज कुमार दुबे

वैश्विक चुनौतियों, बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों, ऊर्जा संकट, आपूर्ति शृंखला की अनिश्चितताओं और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बीच भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बड़े कूटनीतिक मिशन पर निकल रहे हैं। 15 मई से 20 मई तक प्रस्तावित उनकी बहुराष्ट्रीय विदेश यात्रा के दौरान वह संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। यह यात्रा भारत की वैश्विक रणनीति, आर्थिक हितों और सामरिक साझेदारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इस दौरान ऊर्जा सहयोग, व्यापार, हरित प्रौद्योगिकी, रक्षा, निवेश, नवाचार और वैश्विक सुरक्षा जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, जिससे भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमिका और अधिक मजबूत होने की संभावना है।

इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि भारत अपने पारंपरिक मित्र देशों के साथ केवल व्यापारिक संबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति शृंखला जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग को भी विस्तार देना चाहता है। हाल के वर्षों में भारत

ने विश्व मंच पर एक भरोसेमंद और संतुलित शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यही कारण है कि यूरोप और पश्चिम एशिया के देश भारत को भविष्य के आर्थिक और सामरिक साझेदार के रूप में देख रहे हैं।

हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से करेंगे, जहां वह राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग, निवेश, डिजिटल भुगतान, रक्षा और भारतीय समुदाय के कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हुई है। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है तथा बीते पच्चीस वर्षों में भारत में निवेश करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते ने व्यापार को नई गति दी है। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी संयुक्त अरब अमीरात भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी है। इसके अलावा भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा दोनों देशों की सामरिक निकटता को और अधिक मजबूत बना रहा है। वहां रह रहे लाखों भारतीय दोनों देशों के सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की मजबूत कड़ी हैं।



संयुक्त अरब अमीरात के बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे। यह यात्रा भारत और नीदरलैंड के बीच बढ़ते आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी सहयोग को नई दिशा देगी। प्रधानमंत्री वहां के राजा विलेम अलेक्जेंडर, महारानी माक्सिमा और प्रधानमंत्री रोब येटन से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, हरित हाइड्रोजन, जल प्रबंधन, सेमीकंडक्टर और नवाचार जैसे क्षेत्रों में तेजी से सहयोग बढ़ रहा है। नीदरलैंड यूरोप में भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और भारत में बड़े निवेशकों में शामिल है। जल प्रबंधन और कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नीदरलैंड की विशेषज्ञता भारत के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। दोनों देश मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के समर्थन में भी एक समान दृष्टिकोण रखते हैं।

मोदी की स्वीडन की यात्रा भारत और नॉर्डिक देशों के साथ बढ़ते सहयोग की और मजबूत बनाएगी। प्रधानमंत्री गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार, हरित परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उभरती प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग की हम आपको बता दें कि स्वीडन की अनेक प्रमुख कंपनियां भारत में सक्रिय हैं और दोनों देशों के बीच नवाचार आधारित साझेदारी तेजी से विकसित हो रही है। भारत और स्वीडन लोकातांत्रिक मूल्यों, सतत विकास और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में समान सोच रखते हैं। हरित औद्योगिक परिवर्तन और जलवायु संरक्षण के लिए दोनों देशों का सहयोग वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद नॉर्वे जाएंगे, जहां वह तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी और पिछले तैंतालीस वर्षों में भारत से वहां होने वाली पहली प्रधानमंत्री स्तरीय यात्रा भी मानी जा रही

है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्तोरे के साथ होने वाली वार्ता में व्यापार, निवेश, हरित प्रौद्योगिकी और समुद्री अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर रहेगा। भारत और नॉर्वे के संबंध समुद्री सहयोग, हरित ऊर्जा और सतत विकास पर आधारित हैं। भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई गति मिलने की संभावना है। नॉर्वे का विशाल पेंशन कोष भारतीय पूंजी बाजार में महत्वपूर्ण निवेश कर चुका है। आर्कटिक क्षेत्र, हरित जहाजरानी और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में दोनों देशों का सहयोग भविष्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष होगा। इसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के शीर्ष नेता शामिल होंगे। यह मंच भारत और नॉर्डिक देशों के बीच प्रौद्योगिकी, नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, सतत विकास और समुद्री अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों के सहयोग को नई रणनीतिक दिशा देगा। वैश्विक आपूर्ति शृंखला को मजबूत बनाने और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में यह सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मातरैला के साथ उनकी बैठकें

भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगी। दोनों देश 2025 से 2029 तक की संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। इटली ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से अलग होकर भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे को समर्थन दिया है, जिससे दोनों देशों की सामरिक निकटता बढ़ी है। रक्षा क्षेत्र में सह-विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर दिया जा रहा है। इटली भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के प्रयासों का भी समर्थन करता रहा है। वहां रह रहा भारतीय समुदाय दोनों देशों के संबंधों को सामाजिक और सांस्कृतिक मजबूती प्रदान करता है।

इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह विदेश यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की बदलती वैश्विक भूमिका का प्रतीक भी है। यह यात्रा भारत को ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी सहयोग, हरित विकास, रक्षा साझेदारी और वैश्विक व्यापार के नए अवसर प्रदान करेगी। साथ ही यह संदेश भी देगी कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख और विश्वसनीय केंद्र बनकर उभर रहा है।

तमिलनाडु में दूटा द्रविड़ राजनीति का चक्र, नए प्रयोग की बनी डगर

पतन

तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थलापति विजय का मुख्यमंत्री बनना प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। देkhना होगा कि वह केंद्र-राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसे परिपक्वता दिखाते हैं और कैसे सुशासन की स्थायी मिसाल कायम करते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में रविवार का दिन एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में दर्ज हो गया, जब 1967 के बाद राज्य में पहली बार किसी गैर-द्रविड़ दल का मुख्यमंत्री बना है। अफ़िनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय के राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही दशकों से द्रविड़ दलों (द्रमुक और अन्नाद्रमुक) के बारी-बारी सत्ता पर काबिज रहने की परंपरा टूटी है, जो राज्य की राजनीति में नई पीढ़ी और एक नए राजनीतिक विमर्श के प्रवेश का संकेत भी है। उल्लेखनीय है कि 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन इसे सरकार बनाने के लिए दस विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। कांग्रेस के पांच और भाकपा-माकपा के दो-दो विधायकों के समर्थन के बावजूद विजय की पार्टी बहुमत से दूर थी। फिर, बीसीके और आइयूएमएल के समर्थन से आखिरकार अनिश्चितता समाप्त हो गई और राज्य को अपना नौवां मुख्यमंत्री मिल गया। हालांकि दक्षिण भारतीय राजनीति में सिनेमा और राजनीति का मेल नया नहीं है। अन्नादुरई, एम करुणानिधि और एमजीआर से लेकर जयललिता तक तमिल समाज ने फिल्मी सितारों को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक

और राजनीतिक नेतृत्व के तौर पर भी स्वीकार किया है। विजय भी इसी परंपरा की नई कड़ी हैं, जिन्होंने अपनी सार्वजनिक छवि को राजनीतिक दिशा दी और युवाओं के बीच एक प्रभावशाली समर्थन तैयार किया। सिनेमा में भले नायक अकेले ही समस्याओं का समाधान कर देता है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन में निर्णय सामूहिक जिम्मेदारी से लिए जाते हैं। लिहाजा, उनके सामने गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को साथ रखने की चुनौती होगी। तमिलनाडु देश के उन राज्यों में गिना जाता है, जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। ऐसे में, नए मुख्यमंत्री को सुनिश्चित करना होगा कि उनका कम प्रशासनिक अनुभव राज्य के विकास की राह में बाधा न बने। जल संकट, कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याएं और मछुआरों की परेशानियां जैसे मुद्दे तो राज्य के सामने हैं ही, केंद्र-राज्य संबंधों में संतुलन बनाना भी उनकी राजनीतिक परिपक्वता की परीक्षा होगी। एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि विजय की राजनीति अब तक प्रमुखतः भावनात्मक अपील और जनसंपर्क पर आधारित रही है, पर मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद उनसे ठोस नीतिगत दृष्टि की अपेक्षा की जाएगी। लोकतंत्र में हर नया नेतृत्व एक अवसर लेकर आता है। विजय का मुख्यमंत्री बनना भी इसका ही प्रतीक है, जिसमें तमिलनाडु नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। अब यह तो राज्य के नए निजाम और उनकी टीम पर ही निर्भर करेगा कि वे इस अवसर को सुशासन की स्थायी मिसाल में कैसे बदलते हैं।

क्या ‘इंडिया’ गठबंधन के सामने अस्तित्व का संकट है?

पूनम आई. कौशिश

विघटन में एकता या एकता में विघटन ? चकरा गए ? निश्चित रूप से, क्योंकि भाजपा की जीत के बाद विपक्षी दरारें चौड़ी हो गईं और हाल के राज्य चुनावों में टी.एम.सी., द्रमुक, माकपा, की हार के साथ हाताशा घुल-मिल गई। क्या इंडिया ब्लॉक ने अपनी जीवंतता खो दी है ? क्या इसने अपना 'आत्म-विनाश' बटन दबा दिया है ? क्या इसके दिन गिनती के रह गए हैं ? आज पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में हार के बाद ब्लॉक बिखरा हुआ लग रहा है, जो और भी बढ़ सकता है। इस तूफान के केंद्र में, जो ब्लॉक को छिन्न-भिन्न करने की धमकी दे रहा है, इसका सबसे बड़ा घटक कांग्रेस है। पहले से ही, द्रमुक ने अपना अविश्वास स्पष्ट कर दिया है, इसे 'पीठ में छुरा घोंपने वाला' कहा है क्योंकि पुरानी पार्टी (कांग्रेस) नवागंतुक टी.वी.के. के पाले में चली गई।

हालांकि 22 सांसदों वाली द्रमुक ने औपचारिक रूप से ‘इंडिया’ ब्लॉक से अलग होने की घोषणा नहीं की लेकिन यदि यह अब दूरी बनाने का फैसला करती है, तो यह इस मंच के बिखरने और व्यापक विपक्षी अंतरिक्ष के भीतर कांग्रेस के अलगवार की शुरुआत हो सकती है। आज, केरल अपनी झोली में होने के साथ, कांग्रेस 5 में से 3 दक्षिणी राज्यों में सत्ता में है लेकिन अब वह राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य स्थिति में नहीं है। इसलिए, उसे राज्यों के लिए अधिक अधिकारों की मांग करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या वह संघवाद के लिए उसी तरह ठोस तर्क दे सकती है और देगी, जैसा द्रमुक ने दिया था ?

प्रासंगिक रूप से, इंडिया ब्लॉक के भीतर अंतर्विरोध इसके 2023 में गठन के समय से ही हैं। गैर-भाजपा दलों के इस बड़े मंच की कल्पना एक राष्ट्रीय संकट के रूप में की गई थी और इसकी शुरुआत से ही यह स्वीकार किया



गया था कि दल राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगे, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ आएंगे। निश्चित तौर पर, इसने सामूहिक रूप से 2024 के चुनावों में भाजपा को 240 सांसदों पर रोक दिया था लेकिन इस ढीली व्यवस्था की व्यवहारिकता तब उजागर हुई, जब क्षेत्रीय विचारों ने जद (यू) के नीतीश को ब्लॉक छोड़ने और एन.डी.ए. के प्रति वफादारी बदलने के लिए मजबूर किया। पश्चिम बंगाल में ब्लॉक के सदस्यों ने प्रतिस्पर्धा की और एक-दूसरे को काटा। ऐसे पुछा संकेत हैं कि ब्लॉक अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है और 2 या अधिक स्वरूपों में टूट सकता है, जिससे संबोधित करना और उससे उबरना आसान नहीं होगा। अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में विपक्षी एकता का भविष्य धुंधला दिख रहा है।

बंगाल में, कांग्रेस को लगता है कि उसके पास पुनरुत्थान का एक कल्पनिक अवसर है और वह उम्मीद कर रही है कि टी.एम.सी. का एक वर्ग ‘घर वापस’ आ जाएगा। दरअसल, राज्य के नेताओं के बीच अपनी हार के लिए ममता की मंडली को दोषी ठहराते हुए तलवारें झूझखच गई हैं। साथ ही ममता और भतीजे-वारिस अभिषेक बनर्जी के बीच भी चीजें खराब हो गई हैं। कांग्रेस को लगता है कि टी.एम.सी. में भारी पलायन शुरू होने में कुछ महीनों नहीं तो कुछ हफ्तों की ही बात है। एक कांग्रेस-विरोधी मोर्चे के खुलने की संभावना

समाजवादी अखिलेश पर टिकी है। यदि सपा सुप्रीमो ममता और द्रमुक का साथ देने का फैसला करते हैं, तो कांग्रेस को बड़ा झटका लागना प्य है। अगले साल यू.पी. विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सपा प्रमुख के पास एक कठिन विकल्प है-कांग्रेस के साथ जाएं या अकेले। मायावती की बसपा के सपा से हाथ मिलाने के कोई संकेत नहीं होने के कारण, अखिलेश को ममता, केजरीवाल, स्टालिन एंड कंपनी का साथ देने की बजाय कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से ज्यादा फायदा होगा। फिर भी, पुरानी पार्टी द्वारा द्रमुक को छोड़ने के बाद, अखिलेश सतर्क हैं। ऐसा ही हाल राजद के तेजस्वी यादव का भी है। फिर भी सब कुछ खोया नहीं है। गठबंधन अक्सर एक राज्य में टूट जाते हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ जारी रहते हैं। एक सांझी रणनीति वाले चुनावी गठबंधन के रूप में मजबूत होने के बावजूद, ब्लॉक आज बुरी तरह कमजोर हो गया है। एक संसदीय भाजपा-विरोधी मंच के तौर पर यह तकनीकी रूप से अब भी जीवित है। विपक्ष को वह भाषा और शैली ढूंढनी होगी जो भाजपा की निपुणता, बहुआयामी स्वर, चुनाव लड़ने वाली मशीनरी और उन संसाधनों का मुकाबला कर सके, जिनसे वह अपने संचार प्रभुत्व और कथित छवि को मजबूत करती है। मोदी ने पहले ही झूझहटुत्व को ताजा करके, राष्ट्रवाद और देश के स्वाभिमान को परिभाषित और प्रक्षेपित करके चुनौती पेश कर दी है।

बड़ा सवाल : रैली के नारों से परे भाजपा के खिलाफ मोर्चा कौन संभालेगा ? स्पष्ट रूप से, अंतर्विरोधों की इस बारूदी सुरंग में, जहां चुनावी लाभ को ध्यान में रखकर रणनीतियां तैयार की जाती हैं, विपक्ष के लिए आगे की राह बनाने के लिए दूरदर्शिता, चपलता और लचीलेपन की जरूरत होगी। अब तक विपक्ष ने एकता के सद्भाव के बीच केवल एक बिखरा हुआ मोर्चा ही पेश किया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं।

बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ नई उम्मीदें

तस्लीमा नसरीन

पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता में बदलाव के लिए नहीं था, यह लंबे समय से व्याप्त क्षोभ, थकान और धोखा दिए जाने की विस्फोटक प्रतिक्रिया का अवसर भी था। राज्य के लोगों ने सिर्फ भाजपा को जिताने के लिए नहीं, तृणमूल को हराने के लिए भी वोट दिया। जो पार्टी एक समय परिवर्तन का प्रतीक बन गई थी, समय के साथ वह सत्ता के अहंकार, कदाचार और दलीय अंकुश का प्रतीक बन गई थी। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आरोपों की सूची लंबी थी। पार्टी के विरोधी लंबे समय से कह रहे थे कि राज्य में मुस्लिम तुष्टीकरण लगातार बढ़ रही है, पुलिस और प्रशासन पार्टी के पुर्जों के रूप में काम कर रहे हैं, पंचायत से लेकर शीर्ष स्तर तक कदाचार और उगाही ने सांस्थानिक रूप ले लिया है। शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार, कट मनी की दुष्प्रवृत्ति और स्थानीय स्तर पर नेताओं-कार्यकर्ताओं का अज्वाभाविक आर्थिक उत्थान-ये सब आम लोगों को नरवा आ रहे थे। गांवों के लोगों ने देखा कि जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, वे कुछ ही साल में अथाह संपत्ति के मालिक बन बैठे। लोगों में यह धारणा भी बनी कि उद्योग-धंधे, रोजगार और स्थायी विकास पर जोर देने के बजाय लाभार्थी योजनाओं के जरिये वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश की गई। लक्ष्मी भंडार या दूसरी योजनाओं से असंख्य लोगों को लाभ मिलने के बावजूद ममता के विरोधी इसका प्रचार करने में सफल हुए कि विकास के बजाय लाभार्थी योजनाओं के जरिये वोटों की खरीद की राजनीति चल रही है।

सरकारी कर्मचारी भी तृणमूल सरकार से नाराज थे। महंगाई भते के लिए आंदोलन, नौकरी से जुड़े असंतोष और प्रशासन से दूरी ने अनेक शिक्षित, मध्यवर्गीय वोटरों को तृणमूल का विरोधी बना दिया था। सत्ताधारी दल के आतंक, बूथों पर कब्जे, विरोधियों पर हमले और चुनावी अराजकता के आरोपों के कारण लोगों में लोकतंत्र के प्रति क्षोभ और अनास्था की भावना बढ़ रही थी। महिलओं की असुरक्षा, बलात्कार और स्त्री शोषण के मामलों में प्रशासन की भूमिका से भी लोगों में क्षोभ था। सबसे बड़ी बात कि लोगों के एक वर्ग की यह धारणा बन गई थी कि ममता बनर्जी अब पहले की तरह थोड़ा नैंगी नहीं रहें। लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण उनके चारों तरफ व्यक्तिपूजा, अति केंद्रीकरण और सत्ता के अहंकार का वातावरण तैयार हुआ है। इतिहास में कई बार यह देखा



गया है कि कोई सरकार तभी हारती है, जब जनता को लगने लगता है कि सत्तासीन सरकार अब उनकी बातें नहीं सुन रही। प. बंगाल में इस बार इस धारणा ने बड़ी भूमिका निभाई है।

एक समय था, जब बंगाल की पहचान सिर्फ एक भूखंड के तौर पर नहीं, बल्कि एक बौद्धिक सभ्यता के रूप में थी। बंगाल चिंतन और नवजागरण का केंद्र था। राजा राममोहन राय, विवेकानंद, रवींद्रनाथ और सुभाषचंद्र से लेकर सत्यजित राय और महाश्वेता देवी तक बंगाल में प्रतिभाओं की कतार रही है। बंगाल के लेखक, कलाकार सत्ता के अन्याय का विरोध करते थे। रवींद्रनाथ ने अंग्रेजों की नाइटहुड उपाधि लौटा दी थी, सत्ता का विरोध कर नजरूल जेल गए थे। आज का बंगाल क्या उसके अनुरूप है ? अल्पसंख्यक तुष्टीकरण पर भी बंगाल में क्षोभ था। अनेक लोगों की धारणा थी कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, मंदिरों में तोड़-फोड़, घरों और जमीनों पर जबरन कब्जे की खबरें लगातार पश्चिम बंगाल पहुंचती रहीं। इस कारण पश्चिम बंगाल के अनेक हिंदुओं में मौलवियों की संख्या और उनके असर में हुई वृद्धि के कारण यह आशंका पैदा हुई कि राजनीतिक हित साधने के लिए कट्टरवाद को बढ़ावा देने से सामाजिक संतुलन नष्ट होगा। हिंदुओं में व्याप्त यह आतंक सच हो या अतिरंजित-चुनाव में इसका असर पड़ा हो, तो आश्चर्य नहीं।

दूसरी ओर, बांग्लादेश के कट्टरवादी समूहों ने भाजपा की बंगाल विजय को हिंदुवाद की जीत बताते हुए आलोचना की है। यह उनके दोहरेपन का ही नमूना है। पृथ्वी के ज्यादातर ईसाई, यहूदी या हिंदू बहुसंख्यक देशों ने खुद की धर्मनिरपेक्ष छवि बनाई है। जबकि अनेक मुस्लिम बहुल देशों में इस्लाम ही राष्ट्रधर्म है। यह दोहरापन मुस्लिम समाज के आधुनिकीकरण में रौंदा है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने एक दिन वाम शासन को

सत्ता से हटाया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण माकपा के नेतृत्व में वाम मोर्चा का आम जनता से कोई संबंध नहीं रह गया है। उद्योग-धंधों के मोर्चे पर उदासीनता, पार्टीतंत्र और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाकर जनता ने वाम मोर्चे को हटाया था। उस जनक्षोभ के जरिये तृणमूल परिवर्तन के वादे के साथ सत्ता में आई थी। लेकिन समय के साथ-साथ अनेक लोगों की नजरों में तृणमूल भी उसी रास्ते पर चलने लगी थी। फर्क सिर्फ यह था कि उसने इन मामलों में ज्यादा दुस्साहस और आक्रामकता का परिचय दिया। मैं खुद इस राजनीति का शिकार बनी थी। माकपा ने कट्टरवाद के खिलाफ लिखी मेरी किताबों पर प्रतिबंध लगाया और मुझे पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए भी मजबूर किया था। तृणमूल ने भी मुझे वहां रहने नहीं दिया। मेरी किताबों के कार्यक्रम बंद किए गए, मेरी रचनाओं पर आधारित टीवी धारावाहिक के प्रसारण पर रोक लगाई गई। यह सिर्फ एक लेखक पर हमला नहीं था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रश्न पूछने के अधिकार पर हमला था। मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं हूँ, न ही किसी दल की अंध समर्थक हूं। मेरा मानना ​​है कि कोई भी पार्टी आलोचना के दायरे से बाहर नहीं है। जो अच्छा काम करेगी, उसकी प्रशंसा और जो गलत काम करेगी, उसका विरोध करना होगा। नागरिकों का पहला दायित्व किसी दल के प्रति अंधभक्ति के बजाय अपने विवेक को जगाए रखना है।

लोगों ने चूँकि बदलाव की उम्मीदों से वोट दिया है, इसलिए उनकी उम्मीदें भी विराट हैं। वे चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, भय के माहौल पर विराम लगे, प्रशासन निरपेक्ष हो, नौकरियों में पारदर्शिता आए, उद्योग और निवेश बढ़े, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। वे चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल एक बार फिर चिंतन, संस्कृति, कला, साहित्य एवं मानवीयता का उज्ज्वल दृष्टांत पेश करे। पर सिर्फ सरकार बदलने से समाज नहीं बदलता। समाज तब बदलता है, जब लोग खुद में बदलाव लाते हैं। पश्चिम बंगाल के सामने आज बड़ा सवाल है- क्या यह फिर अपने उदार, तार्किक और मानवतावादी स्वर्णिम दौर में लौटेगा या ध्रुवीकरण, घृणा और प्रतिशोध की राजनीति की ओर बढ़ेगा ? बंगाल ने कभी नवजागरण की दिशा दिखाई थी, उदार चिंतन का साहस दिया था, साहित्य और संस्कृति की नई भाषा दी थी। उस बंगाल से लोगों को आज भी उम्मीदें हैं।

शादी के बाद एक्स की याद क्यों आती है? जानिए रिश्ते पर इसका असर

शादी जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें दो लोग रिश्ते में आते हैं और मिलकर नई यादें बनाना शुरू करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस नए सफर के बीच में पुराने रिश्तों की यादें मन में दस्तक देने लगती हैं। आप अपने जीवनसाथी से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन उसके बाद भी आपको अपने एक्स या पुराने प्यार की याद आ जाती है। यह अनुभव कई लोगों को कन्फ्यूज कर देता है, साथ ही अपराधबोध का कारण भी बन सकता है। लोग सोचने लगते हैं कि क्या वे अपने वर्तमान रिश्ते के साथ पूरी तरह ईमानदार हैं या नहीं।

असल में एक्स की याद आना हमेशा इस बात का संकेत नहीं होता कि आप अपने वर्तमान पार्टनर से खुश नहीं हैं। यह एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी हो सकती है, जहां हमारा दिमाग पुरानी यादों और भावनाओं को समय-समय पर दोहराता है। हालांकि अगर ये यादें बहुत ज्यादा हावी होने लगे, तो यह आपके शादीशुदा रिश्ते पर असर डाल सकती हैं।

शादी के बाद एक्स की याद क्यों आती हैं, इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक कारण क्या हो सकता है? ये भी समझें कि इसका असर रिश्ते पर होगा या नहीं।

अधूरी भावनाएं
शादी के बाद भी एक्स पार्टनर की याद आने की सबसे बड़ी वजह होती है, अधूरी भावनाएं। यानी अगर आपका पिछला रिश्ता बिना क्लोजर के खत्म हुआ था तो



उसकी भावनाएं मन में रह सकती हैं। अगर आप किसी से प्यार करते थे, उसके साथ रहना चाहते थे लेकिन किन्हीं कारणों से आपकी शादी आपके एक्स के साथ न हो पाई हो तो भी आप शादी के बाद समय समय पर अपने उस रिश्ते और भावनाओं को मन में रखते हैं जो याद बनकर अक्सर आपके वैवाहिक जीवन में आने लगती है।

शादी के बाद जब जीवन स्थिर होता है, तब दिमाग उन अधूरे पलों को याद करने लगता है। यह एक तरह का इमोशनल बैकलॉग होता है, जो समय-समय पर सामने आता है।

तुलना करने की आदत कभी-कभी लोग अनजाने में अपने एक्स और वर्तमान पार्टनर की तुलना करने लगते हैं। यह तुलना छोटी-छोटी बातों से शुरू होती है, जैसे व्यवहार, आदतें या रोमांस। यही तुलना धीरे-धीरे

एक्स की यादों को ट्रिगर कर सकती है।

दिमाग का ‘नॉस्टेल्जिया इफेक्ट’
नॉस्टेल्जिया इफेक्ट का मतलब है, अतीत की यादों में खो जाना, और उन यादों के जरिए सुखद और सकारात्मक महसूस करना। ये ईंसानों के नेचर में होता है कि उनका दिमाग अक्सर पुराने अच्छे पलों को ज्यादा याद रखता है और बुरे अनुभवों को पीछे छोड़ देता है। इस वजह से एक्स के साथ बिताए अच्छे पल ज्यादा याद आते हैं, जिससे लगता है कि वो रिश्ता बेहतर था। भले ही वास्तव में ऐसा न भी हो। अच्छे पलों की बातें आपको वर्तमान में भी उन यादों से बाहर नहीं निकलने देती हैं।

एक्स से टकराना
कई बार जब आपका अतीत आपके सामने आ जाता है, तो भी पुरानी यादें वापस से आपके जहन में आ जाती हैं। जैसे पुराने दोस्तों से बातचीत में एक्स का जिक्र

होना। सोशल मीडिया के जरिए जब एक्स को अपने वर्तमान जीवन में खुश या दुखी देखना, या कभी किसी मोड़ पर एक्स पार्टनर से अचानक सामना हो जाने पर आप उनकी यादों में खो जाते हैं और उनके जीवन के बारे में जानने की इच्छा आपको बार बार एक्स पार्टनर की याद दिलाता है।

एक्स की याद आने से शादी पर असर पड़ सकता है?

अगर एक्स की यादें केवल कभी-कभार आती हैं, तो यह सामान्य है। लेकिन अगर आप अपने वर्तमान पार्टनर से दूरी महसूस करने लगे, या भावनात्मक दूरी महसूस करने लगे हैं तो यह रिश्ते में दरार ला सकता है। ऐसे में आत्म-चिंतन और खुला संवाद जरूरी है। अपने जीवनसाथी से दूरी पर एक्स की यादों में खो जाने से आप अपने वर्तमान रिश्ते से और दूर होते चले जाते हैं।

एक्स की याद आए तो क्या करना चाहिए?

सबसे जरूरी है कि आप ये समझें कि आपको एक्स की याद आ क्यों रही है। याद आने में कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा करने से अपने जीवनसाथी से दूर हो रहे हैं तो ये गलत है। जरूरी है कि अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। पुराने रिश्ते को क्लोज करने की मानसिक कोशिश करें। अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें दबाएं नहीं। जरूरत हो तो काउंसलिंग लें। खुद को वर्तमान में जीने के लिए ट्रेन करें।

मां बनने का फैसला लेने से पहले खुद से पूछें ये 4 जरूरी सवाल



बदलते समय में अब कई महिलाएं अपने करियर, मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और जीवन की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए मातृत्व के बारे में सोचती हैं। लेकिन समाज का दबाव कई बार उनके आत्मविश्वास और फैसलों पर असर डालता है।

दरअसल, यह विषय आज की पीढ़ी के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि यह सीधे आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है। इसलिए मां बनने का फैसला कभी भी समाज के दबाव में आकर नहीं लेना चाहिए।

अगर आप प्रेशर में आकर कोई फैसला लेंगी तो हो सकता है इससे आपको दिक्कत हो। ऐसे जरूरी है कि मां बनने का फैसला लेने से पहले हर महिला खुद से कुछ अहम सवाल पूछे।

पहला सवाल

सबसे पहले सवाल आता है कि क्या मैं मानसिक रूप से तैयार हूँ? इसका मतलब सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि तनाव, नींद की कमी, लगातार जिम्मेदारियों और भावनात्मक उतार-चढ़ाव को

संभालने की क्षमता से है। मां बनने के बाद जीवन पूरी तरह बदल जाता है, इसलिए मानसिक स्थिरता बेहद जरूरी होती है।

दूसरा सवाल

दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या मेरा शरीर इसके लिए तैयार है? दरअसल, हर महिला का शरीर अलग होता है और गर्भावस्था एक गहरा शारीरिक बदलाव लेकर आती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह, हेल्थ चेकअप और शरीर की स्थिति को समझना बेहद जरूरी है, ताकि आगे किसी तरह की जटिलता न हो।

संभालने की क्षमता से है। मां बनने के बाद जीवन पूरी तरह बदल जाता है, इसलिए मानसिक स्थिरता बेहद जरूरी होती है।

तृतीय सवाल

तृतीय सवाल है कि क्या मैं मां बनने के बाद अपने करियर और शैक्षणिक लक्ष्यों को संभाल पाऊंगी? मां बनने के बाद जीवन पूरी तरह बदल जाता है, इसलिए मानसिक स्थिरता बेहद जरूरी होती है।

लड़के अक्सर नहीं बताते ये सच, रिश्ते में आ सकती है दूरी

हर रिश्ता भरोसे और ईमानदारी की नींव पर टिका होता है। जब दो लोग एक-दूसरे के करीब आते हैं तो उम्मीद की जाती है कि दोनों अपनी भावनाओं और जिंदगी की जरूरी बातों को खुलकर साझा करेंगे। लेकिन कई बार रिश्तों में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें लोग जानबूझकर छुपाते रहते हैं। खासकर लड़के अक्सर अपनी कुछ आदतों, भावनाओं या पेशानियों को जाहिर नहीं करते, जो आगे चलकर रिश्ते में बड़ी समस्या बन सकती हैं।

कई बार शुरुआत में ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही चीजें विश्वास संबंधी समस्याएं, गलतफहमी और भावनात्मक दूरी की वजह बन जाती हैं।

हालांकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, लेकिन अगर आपका पार्टनर बार-बार कुछ जरूरी बातें छुपाता है या खुलकर बात करने से बचता है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यहां जानिए ऐसी 5 बातों के बारे में जिन्हें लड़के अक्सर छुपाते हैं और जो किसी भी रिश्ते के लिए रेड फ्लैग साबित हो सकती हैं।

अपनी असली भावनाएं नहीं बताते
कई लड़के अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं करते। वे दुख, तनाव या असुरक्षा जैसी भावनाओं को अंदर ही दबाकर रखते हैं। शुरुआत में यह सामान्य लग सकता है, लेकिन लंबे समय तक बातचीत की कमी रिश्ते में दूरी पैदा कर सकती है। अगर पार्टनर अपनी भावनाएं कभी साझा नहीं करता, तो यह भावनात्मक अलगाव का संकेत हो सकता है।

वित्तीय समस्याएं छुपाना

रिश्तों में पैसों से जुड़ी सच्चाई



लिए रेड फ्लैग साबित हो सकती हैं।
अपनी असली भावनाएं नहीं बताते
कई लड़के अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं करते। वे दुख, तनाव या असुरक्षा जैसी भावनाओं को अंदर ही दबाकर रखते हैं। शुरुआत में यह सामान्य लग सकता है, लेकिन लंबे समय तक बातचीत की कमी रिश्ते में दूरी पैदा कर सकती है। अगर पार्टनर अपनी भावनाएं कभी साझा नहीं करता, तो यह भावनात्मक अलगाव का संकेत हो सकता है।

लुपाना भी एक बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है। कुछ लोग अपनी आय, कर्ज या आय संबंधित संघर्ष के बारे में खुलकर बात नहीं करते। बाद में यही चीजें झगड़े और भरोसे से जुड़ी समस्याओं की वजह बन सकती हैं। स्वस्थ रिश्ते में वित्तीय पारदर्शिता भी जरूरी मानी जाती है।
पुरुष रिश्ते की सच्चाई छुपाना
कई बार लड़के अपने पुराने रिश्तों या ब्रेकअप की असली वजह बताने से बचते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार-बार अपने बीते हुए कल को छुपाने की कोशिश करे या सवालों से बचता रहे, तो यह चिंता

की बात हो सकती है। रिश्ते में ईमानदारी बेहद जरूरी होती है और अधूरी जानकारी कंप्यूजन पैदा कर सकती है।

कमिटमेंट को लेकर कंप्यूजन
कुछ लोग रिश्ते में रहते हुए भी भविष्य की योजनाओं को लेकर स्पष्ट नहीं होते। अगर आपका पार्टनर कमिटमेंट, शादी या लॉन्ग टर्म प्लान की बातों से हमेशा बचता है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह रिश्ते को लेकर पूरी तरह गंभीर नहीं है। ऐसे बर्ताव को नजरअंदाज करना आगे चलकर भावनात्मक दर्द दे सकता है।

फोन और सोशल मीडिया को जरूरत से ज्यादा सीक्रेट रखना
हर किसी की प्राइवसी जरूरी होती है, लेकिन अगर कोई पार्टनर अपने फोन, चैट्स या सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर जरूरत से ज्यादा रहस्यमयी हो, तो यह भी रेड फ्लैग हो सकता है। लगातार चीजें छुपाना रिश्ते में शक और असुरक्षा बढ़ा सकता है। भरोसा किसी भी मजबूत रिश्ते की सबसे जरूरी कड़ी होती है।

बेटे की शादी के लिए लड़की तलाश रहे हैं? इन गुणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें

हर माता-पिता का सपना होता है कि उनके बेटे की शादी ऐसी लड़की से हो, जो परिवार को प्यार और समझदारी से जोड़कर रखे। आज के समय में शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का रिश्ता मानी जाती है। ऐसे में जीवनसाथी चुनते समय सिर्फ सुंदरता, नौकरी या पढ़ाई पर ध्यान देना काफी नहीं होता। रिश्ते को लंबे समय तक मजबूत और खुशहाल बनाए रखने के लिए कुछ खास गुणों का होना भी बेहद जरूरी माना जाता है।

कई बार लोग जल्दबाजी या बाहरी चीजों को देखकर फैसला कर लेते हैं, लेकिन बाद में छोटी-छोटी बातों पर रिश्तों में तनाव बढ़ने लगता है। इसलिए बेटे के लिए लड़की चुनते समय उसके स्वभाव, सोच, व्यवहार और पारिवारिक मूल्यों को समझना बेहद जरूरी है।

एक अच्छी जीवनसाथी वही होती है, जो मुश्किल समय में साथ निभाए, परिवार का सम्मान करे और रिश्तों को प्यार से संभाल सके। आज के मॉडर्न दौर में यह भी जरूरी है कि दोनों की सोच



और लाइफस्टाइल एक-दूसरे से मेल खाती हो। आइए जानते हैं ऐसे जरूरी गुण, जिन पर बेटे की शादी के लिए लड़की तलाशते समय जरूर ध्यान देना चाहिए।
स्वभाव और व्यवहार पर दें सबसे ज्यादा ध्यान

किसी भी रिश्ते की नींव अच्छे व्यवहार और समझदारी पर टिकी होती है। लड़की तलाशते समय जरूर ध्यान देना चाहिए।
स्वभाव और व्यवहार पर दें सबसे ज्यादा ध्यान
किसी भी रिश्ते की नींव अच्छे व्यवहार और समझदारी पर टिकी होती है। लड़की तलाशते समय जरूर ध्यान देना चाहिए।

है।
परिवार के प्रति सम्मान होना जरूरी

एक अच्छी जीवनसाथी वही मानी जाती है, जो अपने साथ-साथ दूसरे परिवार का भी सम्मान करे। शादी के बाद लड़की का परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बैठाना काफी अहम होता है। अगर लड़की परिवार की भावनाओं को समझती है और बड़ों का आदर करती है, तो घर का माहौल खुशहाल बना रहता है।

सौच और जीवनशैली का मेल
आज के समय में पति-पत्नी की सोच और जीवनशैली का मेल

होना बेहद जरूरी माना जाता है। करियर, भविष्य, बच्चों और परिवार को लेकर दोनों की सोच मिलती-जुलती होनी चाहिए। इससे रिश्ते में कम विवाद होते हैं और समझदारी बढ़ती है। शादी से पहले खुलकर बातचीत करना फायदेमंद माना जाता है।

जिम्मेदार और समझदार
शादी के बाद जीवन में कई जिम्मेदारियां आती हैं। ऐसे में लड़की का जिम्मेदार और समझदार होना बेहद जरूरी है। वह मुश्किल परिस्थितियों को कैसे संभालती है, यह बात रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करती है। आर्थिक समझ और फैसले लेने की क्षमता भी आज के समय में अहम मानी जाती है।

ईमानदारी और भरोसा
हर मजबूत रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है। लड़की का ईमानदार और भरोसेमंद होना बेहद जरूरी माना जाता है। रिश्ते में खुलापन और सच्चाई होने से गलतफहमियां कम होती हैं और वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है।

गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को कैसे रखें व्यस्त? ये तरीके आएं आपके काम

गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए आराम और मस्ती का समय होती हैं, लेकिन आज के डिजिटल दौर में यह समय अक्सर मोबाइल और टीवी तक सीमित होकर रह जाता है। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहने से बच्चों की सेहत, आंखों और मानसिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में माता-पिता के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे बच्चों को कुछ रचनात्मक और एक्टिव गतिविधियों में शामिल करें।

बच्चों के माता-पिता को ये समझना चाहिए कि छुट्टियों को सिर्फ समय बिताने का नहीं, बल्कि नई चीजें सीखने और खुद को विकसित करने का अवसर बनाना जा सकता है। अगर सही तरीके से प्लान किया जाए, तो बच्चे इन छुट्टियों में न सिर्फ एंजाय करेगे बल्कि नई स्किल्स भी सीखेंगे।

इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और मजेदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर



रखकर उनकी छुट्टियों को प्रोडक्टिव और यादगार बना सकते हैं।

आउटडोर गेम्स में शामिल करें

बच्चों को क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, साइकिलिंग या पास के पार्क में खेलने के लिए प्रेरित करें। इससे उनकी शारीरिक फिटनेस बेहतर होती है, ऊर्जा सही दिशा में लगती है और उनका स्क्रीन टाइम भी कम होता है।

आउटडोर खेल बच्चों में टीमवर्क और अनुशासन भी सिखाते हैं।

क्रिएटिव एक्टिविटीज

ड्राइंग, पेंटिंग, पेपर क्राफ्ट और DIY प्रोजेक्ट्स जैसी गतिविधियों में बच्चों को शामिल करें।

इससे उनकी कल्पनाशक्ति, फोकस और हाथों की क्रिएटिव स्किल्स बढ़ती हैं।

बच्चे अपने विचारों को रंगों और आकारों के माध्यम से व्यक्त करना सीखते हैं।

किताबें पढ़ने की आदत स्ठोरी बुक्स, कॉमिक्स और ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करें।

इससे उनकी भाषा, शब्दावली और सोचने की क्षमता मजबूत होती है।

पढ़ने की आदत उन्हें मोबाइल से दूर रखने में भी मदद करती है। नई स्किल सीखें
गर्मियों की छुट्टियां नई चीजें सीखने का बेहतरीन समय होती हैं।

बच्चे डांस, म्यूजिक, कुकिंग, कंप्यूटर बेसिक्स या कोई नई भाषा सीख सकते हैं।

इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और भविष्य के लिए नई संभावनाएं खुलती हैं।

फैमिली टाइम
बोर्ड गेम्स जैसे लूडो, कैरम, शतरंज खेलें या फैमिली पिकनिक और छोटी ट्रिप प्लान करें।

इससे बच्चों को परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलता है और रिश्ते मजबूत होते हैं।

गार्डनिंग और नेचर एक्टिविटी
बच्चों को पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करें। इससे उनमें जिम्मेदारी की भावना आती है और वे प्रकृति के करीब रहते हैं। यह एक्टिविटी उन्हें शांत और धैर्यवान भी बनाती है।

18 साल का होने वाला है बेटा? ये जरूरी बातें जरूर बताएं

हर माता-पिता के लिए उनका बच्चा हमेशा छोटा ही रहता है, लेकिन जब बेटा 18 साल का होने वाला होता है, तो जिंदगी का एक बड़ा मोड़ सामने खड़ा होता है। यह उम्र सिर्फ कानूनी तौर पर वयस्क बनने की नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों, फैसलों और आत्मनिर्भरता की शुरुआत भी होती है।

करियर प्लान

इस दौर में सही मार्गदर्शन मिलना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यही वो समय है जब बच्चे अपने जीवन के अहम फैसले लेने लगते हैं, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत आदतें। अगर इस समय माता-पिता खुलकर और समझदारी से अपने बेटे से कुछ जरूरी बातें साझा करें, तो यह उसकी जिंदगी को सही दिशा दे सकता है।

कई बार हम सोचते हैं कि बच्चे खुद ही सब समझ जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें अनुभव



और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इस लेख में हम आपको बताएंगे 5 ऐसी अहम बातें, जो हर माता-पिता को अपने 18 साल के होने वाले बेटे से जरूर करनी चाहिए, ताकि वह एक जिम्मेदार और सफल इंसान बन सके।
जिम्मेदारी लेना सीखें
अब वह बच्चा नहीं रहा, उसे

अपने फैसलों की जिम्मेदारी समझनी होगी। छोटे-छोटे काम जैसे अपनी खर्च संभालना, समय का सही उपयोग करना और घर के कामों में योगदान देना उसे जिम्मेदार बनाते हैं।
पैसों की वैल्यू समझाएं
कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से

खर्च और बचत करना। बजट बनाना, अनावश्यक खर्च से बचना और भविष्य के लिए सेविंग करना, ये आदतें उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगी।

सही दोस्त और रिश्ते चुनना

इस उम्र में दोस्ती और रिश्ते बहुत प्रभाव डालते हैं। उसे सिखाएं कि किस तरह सकारात्मक और भरोसेमंद लोगों के साथ रहना चाहिए और गलत संगत से बचना चाहिए।

डिजिटल लाइफ का सही इस्तेमाल

सोशल मीडिया और इंटरनेट का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। उसे बताएं कि ऑनलाइन व्यवहार, प्राइवसी और समय की बर्बादी से कैसे बचा जा सकता है।

असफलता से डरे नहीं, सीख लें

हर किसी को जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। उसे समझाएं कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने का मौका है। यही सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत देगी।

नई दिल्ली में ब्रिक्स: विदेश मंत्रियों की बैठक का आगाज

नई दिल्ली। नई दिल्ली में 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। भारत इस साल 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, और



इसी कड़ी में इस दो दिवसीय आयोजन में सदस्य देशों तथा कई आमंत्रित राष्ट्रों के वरिष्ठ राजनयिकों का जमावड़ा लगा है। बैठक का उद्देश्य वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करना। इस बैठक में ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। संयुक्त अरब अमीरात का प्रतिनिधित्व उप-विदेश मंत्री स्तर पर होने की उम्मीद है, जबकि चीन के शेरपा का प्रतिनिधिमंडल इसमें शिरकत करेगा। दक्षिण अफ्रीका के अंतरराष्ट्रीय संबंध मंत्री रोनाल्ड ओजी लामोला मंगलवार को और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगिओनो बुधवार को नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। ईरान ने भी अपने विदेश मंत्री अब्बास अराघची के शामिल होने की सूचना दी है।

नीट मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, प्रक्रिया पर उठा सवाल

नई दिल्ली। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफएआईएमए) ने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए परीक्षा

प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और बड़े सुधारों की मांग की है। एफएआईएमए ने कहा कि पिछले कुछ समय से नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। खासकर पेपर लीक, तकनीकी गड़बड़ियों और पारदर्शिता की कमी जैसी शिकायतों ने लाखों छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर किया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी वजह से संगठन ने मांग की है कि नीट यूजी 2026 की पूरी प्रक्रिया को या तो दोबारा कराया जाए या फिर इसे न्यायिक निगरानी में कराया जाए, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। याचिका में सबसे बड़ा मुद्दा एनटीए को लेकर उठया। एफएआईएमए ने कहा कि पिछले कुछ सालों में एनटीए की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठते रहे हैं।

पीएम मोदी की अपील मानने को तैयार नहीं सांसद महतो

धनबाद। खाड़ी देशों से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बाधित होने और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ते दबाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन की खपत कम करने की विशेष अपील की है।

प्रधानमंत्री ने नेताओं और मंत्रियों से भी आग्रह किया है कि वे अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करें ताकि राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन बचाए जा सकें। इस अपील के बाद जहां कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले छोटे किए हैं, वहीं धनबाद में इसे लेकर अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। धनबाद के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री की पहल का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे स्वयं अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटाकर इस बचत मुहिम को हिस्सा बनेंगे। हालांकि, इसी दौरान उनके बगल में बैठे धनबाद के भाजपा सांसद दुलू महतो ने इस मुद्दे पर अपनी गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का हवाला दिया।

सीएम के लिए वेणुगोपाल के नाम पर भड़के लोग

वायनाड। केरल में हालिया विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को मिली शानदार जीत के बावजूद, मुख्यमंत्री पद के चयन को लेकर गठबंधन में गतिरोध जारी है। सत्ता में आने के 10 दिन बाद भी, इस खींचतान ने पार्टी के भीतर गहरी फूट पैदा कर दी है, जिसका गुस्सा अब वायनाड की सड़कों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सीएम पद के चेहरे को लेकर चल रही इस तनातनी के बीच, वायनाड डीसीसी कार्यालय के पास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड़ा को निशाना बनाने वाले गुमनाम पोस्टर सामने आए हैं केरल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में केंसी वेणुगोपाल को आगे बढ़ाने के संभावित कदम के खिलाफ जनता का विरोध लगातार बढ़ रहा है। अंग्रेजी में लिखे इन पोस्टरों में राहुल और प्रियंका के आरोप लगाया गया है कि वे केंसी वेणुगोपाल को केरल पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ व्यापक जनभावना मौजूद है। इनमें से एक पोस्टर चेतावनी देता है कि केरल आपकों कभी माफ नहीं करेगा, जबकि दूसरा पोस्टर एक अशुभ घोषणा करता है कि वायनाड दूसरा अमेठी बन जाएगा।

सोनिया गांधी रूटीन चेकअप के बाद घर लौटें

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को रूटीन चेकअप के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचीं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि जांच के बाद वह घर लौट आई हैं। सूत्रों के

मुताबिक सोनिया गांधी को मंगलवार रात करीब 10:30 बजे मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजैस्टिव एंड हेपेटोबिलियरी साइंसेज में भर्ती कराया गया था। हालांकि, अस्पताल की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इससे पहले 24 मार्च को बुखार और संक्रमण के कारण उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहां वह 7 दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रही थीं। राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को जनवरी से अब तक तीसरी बार भर्ती होना पड़ा है। इससे पहले मार्च में उन्हें सर गंगाराम अस्पताल ले जाया गया था। पेट में इंफेक्शन से जुड़ी समस्या बताई थी, जिसके इलाज के लिए वह वहां पहुंची थीं। वहीं जनवरी में उन्हें सांस लेने में समस्या हुई थी।

मोदी सरकार ने दिया किसानों को दिया बड़ा तोहफा

खरीफ की 14 फसलों पर बढ़ाई एमएसपी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में बुधवार को आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।

सरकार ने वर्ष 2026-27 के विपणन सत्र के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि सूरजमुखी के बीज (7622 प्रति क्विंटल) के लिए, उसके बाद कपास (2557 प्रति क्विंटल), नाइजरसीड (2515 प्रति क्विंटल) और तिल (2500 प्रति क्विंटल) के लिए अनुशंसित की गई है।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 37,500 करोड़ रुपये से कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने की एक योजना को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, कोयला गैसीकरण का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। गैस की आवश्यकता और भू-राजनीतिक स्थिति के अनुसार आत्मनिर्भर कैसे बनें ?

उन्होंने कहा, भारत में कोयले का प्रचुर भंडार है। अगले 200 वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के पास पर्याप्त कोयला है। तो क्या हम उस कोयले का उपयोग करके गैस का उत्पादन कर सकते हैं? इस दिशा में अच्छा प्रयास किया जा रहा था और आज एक निर्णय लिया गया है – कोयला गैसीकरण योजना। कोयले से गैस का उत्पादन और फिर उस गैस से उर्वरक, कोयले से गैस का उत्पादन और फिर उस गैस से निजली, कोयले से गैस का उत्पादन और फिर उस गैस से विभिन्न प्रकार के रसायन। यह एक बड़ा निर्णय है।

वैष्णव ने बताया कि रेल मंत्रालय की लगभग



20,667 करोड़ रुपये की लागत वाली अहमदाबाद (सरखेज)– धोलेरा अर्ध-उच्च गति दोहरी लाइन परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। भारत की पहली सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना के रूप में, यह परियोजना एक अग्रणी परियोजना के रूप में काम करेगी और देश भर में सेमी हाई-स्पीड रेल के चरणबद्ध विस्तार के लिए एक संदर्भ मॉडल के रूप में कार्य करेगी।

यह स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से निर्मित भारतीय रेलवे की पहली अर्ध-उच्च गति परियोजना होगी। इस परियोजना खंड से अहमदाबाद, धोलेरा एसआईआर, आगामी धोलेरा हवाई अड्डे और लोथल राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर (एनएचएमसी) के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। अहमदाबाद को धोलेरा से जोड़ने से यात्रियों का यात्रा समय कम होगा, जिससे दैनिक आवागमन आरामदायक होगा और एक ही दिन में वापसी यात्रा संभव हो सकेगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत निजी भागीदार को शामिल करते हुए दीर्घकालिक लाइसेंस के जरिए नागपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है।

खेल प्रमुख समाचार

पंजाब किंग्स और मुम्बई इंडियंस के बीच मुकाबला आज मुंबई। मुम्बई इंडियंस टीम का प्रदर्शन



आईपीएल के इस सत्र में अच्छा नहीं रहा है और टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गयी है। टीम को अब गुरुवार को बचे हुए लीग मैच में पंजाब किंग्स से खेलना है। मुम्बई की टीम इस मैच में जीत के साथ ही अपना खोया मनोबल हासिल करने का प्रयास करेगी। टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन भी इस सत्र में अच्छा नहीं रहा और वह आलोचकों के निशाने पर हैं। पांड्या फिट नहीं होने के कारण पिछले दो मैचों से बाहर थे। अब उनका लक्ष्य गुरुवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर लय हासिल करना चाहेंगे। इसी को देखते हुए पांड्या अकेले ही नेट्स में अभ्यास करते दिखे। इससे साफ है कि वह पंजाब के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे।

हार्दिक इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में नहीं उतरे थे। पीट की समस्या के कारण उनकी अनुपस्थिति ने टीम के संतुलन और प्रदर्शन को काफी प्रभावित किया है, खासकर जब टीम इस सीजन में लगातार संघर्ष कर रही है। मुंबई पहले ही आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जिसके बाद टीम के भीतर और बाहर कई सवाल उठे हैं। इन हालातों के बीच, पांड्या ने टीम के भविष्य और रणनीति पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, टी20 क्रिकेट में उठार-चढ़ाव आना तय है। जब सीजन खत्म हो जाएगा, तब सही समय होगा कि क्या गलत हुआ, इसका सही आकलन किया जाए। लेकिन इस समय मेरी राय है कि सीनियर खिलाड़ियों ने अपनी पूरी कोशिश की है। पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाला यह मैच मुंबई इंडियंस के लिए अंक तालिका में केवल एक औपचारिकता है। मुंबई का लक्ष्य अब सम्मानजनक प्रदर्शन करते हुए अपने अभियान का अंत करना होगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 49 अंक चढ़ा निफ्टी 23430 पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार ने उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद हल्की बढ़त के साथ दिन का समापन किया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार को मेटल, ऑयल और गैस जैसे सेक्टरों से सपोर्ट मिला, जिससे गिरावट का दबाव कम हो गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 49.74 अंक या 0.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 74,608.98 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33.05 अंक या 0.14 प्रतिशत चढ़कर 23,412.60 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में मेटल, ऑयल एंड गैस और कंप्यूटर ड्यूरेबल्स सेक्टरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इन सेक्टरों में तेजी ने पूरे बाजार को सहारा दिया और गिरावट को सीमित रखा। दूसरी ओर आईटी, ऑटो, बैंक और मीडिया सेक्टरों में गिरावट दर्ज की गई। इन सेक्टरों में बिकवाली का दबाव ज्यादा रहा।

पहली छमाही में वनस्पति तेल का आयात 13% बढ़ा

नई दिल्ली। देश का वनस्पति तेल आयात 2025-26 तेल वर्ष के पहले छह महीनों में 13 प्रतिशत बढ़कर 79.4 लाख टन हो गया। पाम तेल की खेप में तेज उछाल इसकी मुख्य वजह रही। साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) ने बुधवार को यह जानकारी दी। दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल उपभोक्ता भारत ने पिछले वर्ष की समान अवधि (नवंबर-अप्रैल) में 70.4 लाख टन आयात किया था। भारत का तेल वर्ष नवंबर से अक्टूबर तक चलता है। मूल्य के संदर्भ में, नवंबर-अप्रैल अवधि के दौरान आयात सालाना आधार पर 73,000 करोड़ रुपए से 19 प्रतिशत बढ़कर 87,000 करोड़ रुपए हो गया। सघ के अनुसार, कुल आयात में खाद्य तेलों की हिस्सेदारी 78.2 लाख टन जबकि गैर-खाद्य तेल की 1.21 लाख टन रही।

मध्य-पूर्व तनाव से डीएपी के दाम में 40% उछाल

नईदिल्ली। मध्य-पूर्व में जारी तनाव का असर अब भारत की खेती पर भी दिखाई देने लगा है। खेती में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख उर्वरक डायअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। भारत ने अब डीएपी को युद्ध से पहले की तुलना में लगभग 40 फीसदी अधिक कीमत पर खरीदने का समझौता किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन पोटाश लिमिटेड पश्चिमी तट के लिए 7.05 लाख टन डीएपी उर्वरक 930 डॉलर प्रति टन की दर से खरीदेगी, जबकि पूर्वी तट के लिए 6.41 लाख टन उर्वरक 935 डॉलर प्रति टन के भाव पर लिया जाएगा। फरवरी में यही कीमत करीब 667 डॉलर प्रति टन थी। खाद की कीमत बढ़ने का सीधा असर खेती की लागत पर पड़ता है। किसान फसल उत्पादन में बड़ी मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करते हैं। यदि सरकार सस्मिडी नहीं बढ़ाती है, तो किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।

गोल्ड इयूटी बढ़ने से ज्वेलरी इंडस्ट्री को झटका

नईदिल्ली। सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने से रत्न एवं आभूषण उद्योग को आने वाले समय में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और इससे तस्करी को बढ़ावा मिल सकता है। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण परिषद (जीजेसी) के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता उपायों और सर्राफा आयात शुल्क बढ़ने से कारोबार अक कठिन होने वाला है। उद्योग को आशंका है कि इससे तस्करी बढ़ेगी। शुल्क बढ़ोतरी को समझाते हुए रोकड़े ने कहा कि अब सीमा शुल्क, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) और कृषि उपकर को मिलाकर आयात शुल्क के कारण सोना पहले के 13,500 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर लगभग 27,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो सकता है।

गहनों से अधिक निवेश के लिए बढ़ी है सोने की मांग

मधुरेंद्र सिन्हा

भारत में प्राचीन काल से ही लोग स्वर्णाभूषणों के लिए सोने की खरीदारी करते रहे हैं। एक समय हमारा देश सोने के उत्पादन में भी अव्वल था। पर समय बदला और भारत के विश्वविख्यात कोलार खदानों के स्रोत सूख गये। देश को आयात पर निर्भर होना पड़ा, फिर भी सोने के प्रति लोगों की दीवानगी कम नहीं हुई। सोने की बढ़ती खपत को रोकने के लिए 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट बनाया गया था। इसका उद्देश्य सोने के आभूषणों के उत्पादन, वितरण, और भंडारण पर नियंत्रण करना था। इसके तहत जनता के लिए सोने की छड़ों और सिक्कों के रूप में सोना रखना निषिद्ध कर दिया गया। सुनारों को भी सौ ग्राम से अधिक सोना रखने की मनाही थी। इस कानून ने बड़े पैमाने पर तस्करी को जन्म दिया। आखिरकार सरकार

ने 1990 में इस कानून को निरस्त कर दिया। इसके बाद से भारत में सोने के आयात में लगातार वृद्धि होने लगी। वर्ष 2000-2001 में भारत ने 471 टन सोने का आयात किया था, जो 2012-2013 तक 1,000 टन से अधिक हो गया। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में सोने का आयात 721.03 टन रहा। यह आयात हमारे व्यापार घाटे को बढ़ा रहा है। गहने बनाने के अतिरिक्त सोने की वैसी कोई खास उपयोगिता नहीं है। पर एक नयी बात देखने में आ रही है कि अब लोग सोने की खरीदारी गहनों के अतिरिक्त निवेश के लिए भी करने लगे हैं। सोना संकट या अनिश्चित भविष्य का साथी है। सारी दुनिया में लोग सोने को संकट के समय का सहारा मानते हैं। इसलिए युद्ध, दुर्भिक्ष या महामारी के दौरान सोने की कीमत बढ़ जाती है। पिछले कुछ वर्षों में सोने की मांग बढ़ी और उसके दाम बुलंदियों पर जा पहुंचे हैं। इससे



भारतीय भी चौकन्ने हो गये और वे भी अब सोने में निवेश करने लगे हैं। ‘वर्ल्ड गोल्ड कार्डसिल’ की 2026 की पहली तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में निवेश के उद्देश्य से 151 टन सोना खरीदा गया, जो पिछले वर्ष से 10 प्रतिशत अधिक है।

वहीं सोने की छड़ों और सिक्कों की मांग में 54 प्रतिशत की तेजी आयी, जबकि स्वर्णाभूषणों की मांग में 19.5 प्रतिशत की कमी आयी। इस तरह भारत के इतिहास में पहली बार निवेश के लिए सोने की मांग गहनों की मांग से ज्यादा हो गयी। कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच लोगों ने सोने पर

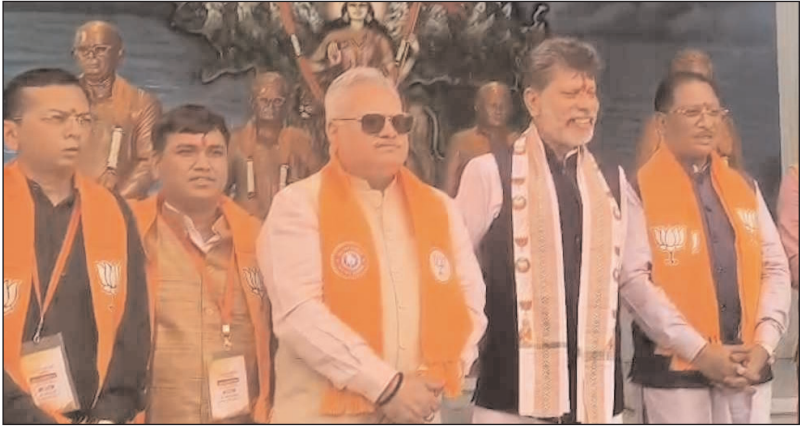
अपना भरोसा जताया। इटीएफ में भी लोगों ने खूब पैसा लगाया। मार्च की तिमाही में इसमें 186 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो ऐतिहासिक थी।

निवेश के लिए ग्राहकों की बढ़ती रुचि के कारण सोने के घरेलू दाम में लाभग्रा दोगनी वृद्धि हो गयी है, जबकि भारतीय शेयर बाजारों से रिटर्न महज 2.5 प्रतिशत ही रहा। सो, इस समय लोग शेयर बाजारों की जगह सोने या रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं। सोने में निवेश से उन्हें मोटे रिटर्न की उम्मीद है, जो संभव भी है। इसके अतिरिक्त, सोने का उत्पादन सीमित है और हर वर्ष 3,500 से 3,600 टन सोने की खुदाई होती है, जिसमें चीन सबसे आगे है। इस वजह से वह इसके दाम भी बढ़ाता जा रहा है। दूसरी ओर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशों में रखा अपना सोना वापस लेता जा रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरियों में भारत का काफी सोना रखा हुआ

है। अब वह इसे वापस ला रहा है, ताकि विदेशी भंडारों पर उसकी निर्भरता न रहे। यह रणनीति दुनियाभर में हो रहे युद्धों के कारण बनायी गयी है। इसका लाभ यह भी है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे विदेशी बैंकों को गोल्ड स्टोरेज चार्ज नहीं देना होगा और हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने में भी यह काम आ सकता है। अगर कोई अंतरराष्ट्रीय इमरजेंसी हो और मुद्रा का अभाव हो जाये, तो अपने पास सोने का बड़ा भंडार होने से किसी भी तरह के आर्थिक प्रतिबंध का मुकाबला किया जा सकता है। फिर विदेशों में रखा सोना वहां फंस भी सकता है। भारत ऐसी स्थिति से बचना चाहता है, ताकि दुनिया अर्थव्यवस्था पर जोर न पड़े। विदेशों में सोना रखने पर उसके इश्योरेंस का पैसा भी देना पड़ता है, जो करोड़ों में होता है। अपना सोना अपने पास रखने से यह बचत हो जायेगी।

भाजपा कार्यसमिति की बैठक: प्रदेश अध्यक्ष सिंह देव बोले-

संगठनात्मक कार्यों की रूपरेखा की गई तय



रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति बैठक का समापन हो गया। राजधानी रायपुर में आयोजित इस अहम बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी रणनीति, राजनीतिक प्रस्तावों और नक्सल उन्मूलन जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। करीब 6 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव,

दोनों डिप्टी सीएम, मंत्रीगण और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हर तीन माह में आयोजित की जाती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार संगठनात्मक कार्यों की रूपरेखा तय की गई है और अब इन्हें निचले स्तर तक प्रभावी तरीके से लागू

किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि संभाग प्रभारियों और जिला प्रभारियों को संभागीय बैठकों में शामिल होने का विशेष टास्क दिया गया है। वहीं जिलाध्यक्षों की अध्यक्षता में जिला कार्यसमिति बैठकों के आयोजन पर भी जोर दिया गया है, ताकि संगठनात्मक गतिविधियों को बृ्थ स्तर तक सक्रिय किया जा सके। बैठक के दौरान सांसद रूप कुमारी चौधरी और वरिष्ठ भाजपा नेता शिवरतन शर्मा ने पक्ष रखा। वहीं प्रदेश में नक्सल उन्मूलन और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विस्तृत प्रस्तुति दी।

कोर कमेट्री के हालिया पुनर्गठन को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि नई टीम में नए और पुराने दोनों चेहरों को जगह दी गई है। उन्होंने इसे संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में अहम कदम बताया।सूत्रों के मुताबिक बैठक में आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों, संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति पर भी मंथन किया गया।

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश में

मजबूत हो रही विद्युत अधोसंरचना

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना को मजबूत बनाने और आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण बिजली सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कबीरधाम जिले के कवर्धा शहर में बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए घोटिया स्थित नवीन बस स्टैंड के पास 33/11 केव्ही विद्युत उपकेंद्र का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं गुह मंत्री श्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत लगभग 2.06 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस उपकेंद्र का भूमिपूजन किया।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शहरों और



ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नया विद्युत उपकेंद्र शुरू होने से आसपास के क्षेत्रों को बेहतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। इस परियोजना से कवर्धा शहर के 13 वार्डों के लगभग 8 हजार 614 उपभोक्ता सीधे लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बनने के बाद पिछले द्वाई वर्षों में जिले में विद्युत अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किए गए

हैं।दलदली, सेमो और सरेखा में नए उपकेंद्रों का भूमिपूजन पहले ही किया जा चुका है तथा दुबहा में भी जल्द नए उपकेंद्र का भूमिपूजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में पांच नए सब स्टेशन स्थापित करने की दिशा में

तेजी से कार्य चल रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि विद्युत आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ट्रांसफार्मरों की संख्या बढ़ने से लो वोल्टेज, ओवरलोड और बार-बार बिजली बाधित होने जैसी समस्याओं में कमी आती है। उन्होंने बताया कि पिछले द्वाई वर्षों में जिले में अब तक 486 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा चुके हैं तथा आने वाले समय में भी यह कार्य जारी रहेगा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह

ने घटाया अपना काफिला



■ प्रधानमंत्री मोदी के

ईंधन संरक्षण की

अपील से प्रेरित होकर

लिया फैसला

रायपुर। छग विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए देशवासियों से की गई अपील का सम्मान करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने अपने प्रोटोकॉल काफिला से 4 वाहनों का उपयोग कम करने का

शासन के मिशन मोड में किए जाने वाले कार्यों

की हुई समीक्षा, दिए जरूरी निर्देश



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा अनुसार छत्तीसगढ़ शासन विशिष्ट क्षेत्रों में तीव्र और लक्षित विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यों को मिशन मोड में संचालित करेगा। इस संबंध में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने लक्षित विकास के लिए नए मिशन शुरू किए हैं, जिन्हें पूरी तरह मिशन मोड में संचालित किया जाएगा। अधिकारियों ने बैठक में अपनी विभागीय योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण के जरिए विस्तार से जानकारी रखी।

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री एआई मिशन के संबंध में बताया कि उपरती हुई तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को देश का अग्रणी राज्य बनाना है। इसके लिए यहां

की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री पर्यटन मिशन के अंतर्गत प्रमुख पर्यटन स्थलों को वैश्विक मानचित्र पर लाने के लिए थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित किए जाएंगे। सांस्कृतिक मेलों, उत्सवों और प्रदर्शनियों का आयोजन तथा स्थानीय स्तर पर ‘होमस्टे’ योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटन के तहत स्थानीय युवाओं को दूर गाइडों के कौशल विकास के जरिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन के जरिए राज्य के बुनियादी ढांचे, सड़कों,

पुलों और शहरी-ग्रामीण कनेक्टिविटी को मिशन मोड में मजबूत करना है। प्रदेश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए अधोसंरचना का तेजी से निर्माण किया जाना है। मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन के तहत प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना और नए व्यापारिक विचारों को जमीन पर उतारना है। नए स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता और सरल प्रक्रियाएं सुनिश्चित की जाएंगी। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव रजत कुमार, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, विशेष सचिव वित्त चंदन कुमार, विशेष सचिव उच्च शिक्षा जय प्रकाश मोर्य सहित सूचना प्रौद्योगिकी एवं चिपस विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

राजधानी में ट्रेड यूनियनों का प्रदर्शन,

गिरफ्तार मजदूरों की रिहाई की मांग

रायपुर। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और अनेक स्वतंत्र संगठनों के संयुक्त आह्वान पर देश भर में असंगठित श्रमिकों पर जारी शोषण और दमन के खिलाफ मंगलवार को राष्ट्रीय मांग दिवस मनाया। इस दौरान नोयडा सहित दिल्ली-एनसीआर में गिरफ्तार मजदूरों की रिहाई की मांग की। इस क्रम में मंगलवार शाम राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में ट्रेड यूनियनो के संयुक्त मंच के नेतृत्व में श्रमिकों और कार्यचरियों ने विरोध प्रदर्शन किया।

इस दौरान संपन्न विरोध सभा को संबोधित करते हुए संयुक्त मंच के संयोजक, आल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। धर्मराज महापात्र ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मानेसर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और देश के अनेक



औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिक अमानवीय शोषण, कम मजदूरी, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों और श्रम के बढ़ते ठेकेदारीकरण के विरुद्ध साहसपूर्वक संघर्ष कर रहे हैं।

सरकारों इन वास्तविक मांगों को संबोधित करने के बजाय दमन, गिरफ्तारियों, धमकियों और श्रमिकों तथा ट्रेड यूनियन नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का रास्ता अपना रही हैं। आज ठेका श्रमिक औद्योगिक कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं।

उन्हें प्रतिदिन 10 से 13 घंटे तक कार्य करना पड़ता है और मात्र ₹10,000 से ₹12,000 प्रतिमाह श्रम के बढ़ते ठेकेदारीकरण के विरुद्ध साहसपूर्वक संघर्ष कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

अग्निवीर उड़ान सेना में भर्ती

के लिए निःशुल्क कोचिंग

रायपुर। देश सेवा का जज्बा रखने वाले युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के लिए धमतरी जिला प्रशासन ने एक सराहनीय पहल की है। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती 2026-27 की तैयारी कर रहे स्थानीय युवाओं के लिए जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का सफल शुभारंभ किया गया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा संचालित यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 07 मई 2026 से सम्पन्नित हो रहा है। वर्तमान में जिले के 25 चयनित अभ्यर्थी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। हाईब्रिड मोड में युवाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाया जा रहा है। परीक्षा की दृष्टि से अहम विषयों जैसे सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जून 2026 में संभावित ऑनलाइन लिखित परीक्षा को देखते हुए छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए नियमित अंतराल पर विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जिले के अधिक से अधिक युवाओं को भारतीय सेना का हिस्सा बनाना है। अक्सर संसाधनों के अभाव या सही दिशा-निर्देश न मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली युवा लिखित परीक्षा में पिछड़ जाते हैं। यह निःशुल्क कोचिंग इसी अंतर को पाटने का एक सशक्त माध्यम बनी है।

केंद्र सरकार के संरक्षण में ही

नीट के पेपर लीक हुये : शुक्ला

रायपुर। लगातार दूसरे साल नीट की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होना मोदी सरकार की विफलता को दर्शाता है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि एक बार भूल हो सकती है लेकिन लगातार दूसरी बार भी नीट के प्रश्न पत्र लीक होना इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार के संरक्षण में यह प्रश्न पत्र लीक का घोटाला किया गया है। नीट देशभर के लाखों बच्चों के न सिर्फ भविष्य उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ



विषय 1 वर्षों तक कठिन मेहनत करके बच्चे नीट की तैयारी करके परीक्षा में सम्मिलित हुये थे। परीक्षा के बाद पेपर लीक की बात सामने आने से विद्यार्थियों की मेहनत पर पानी फिर गया। इस मामले की प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और नीट के कर्ताधर्ता को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पिछली बार भी नीट के पेपर लीक मामले में मोदी सरकार ने किसी की जवाबदेही तय नहीं की, न ही कोई ठोस कार्रवाही किया था। जब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, लाखों बच्चों की मेहनत बर्बाद हुई थी, तब लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए मोदी सरकार ने चाल चली और एनटीए के डीजी को पद से हटा दिया, लेकिन जैसे ही लोगों का गुस्सा शांत हुआ।

बिजली कटौती से जनता

परेशान: ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार पर बेतहाशा बिजली बिल में से जनता को लूटने का आरोप लगाते हुए कहा कि आमजनता महंगी बिजली दर,अधोषित बिजली कटौती में बेतहाशा बिल से परेशान है।सरकार जनता की पीड़ा को सुन नहीं रही है। मनमानी कर रही है। भाजपा सरकार में अब तक चार बार बिजली के दाम बढ़ाये गये है। बिजली बिल हाफ योजना से 400 यूनिट तक मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया गया है। पूर्व में जिन घरों में 400 रु. से 500 रु. बिजली बिल आता था मई माह में उन घरों में 1500 रु. से 3000 रु. तक बिल भेजा गया है। जनता



खपत से ज्यादा बिल आने की शिकायत कर रही है ये स्मार्ट मीटर के चलते उत्पन्न हुई है। स्मार्ट मीटर को लेकर जनता की शिकायत का निराकरण नहीं किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा शहर से लेकर गांवों तक अधोषित बिजली कटौती से घण्टो बिजली बंद हो रही है। लो वोल्टेज की समस्या से बिजली के उपकरण खराब हो रहे, सबमर्सिबल पम्पों से सिंचाई नही हो रही है, पेयजल संकट हो रहा है। भीषण गर्मी में कूलर पंखा चल नही पा रहा है। भाजपा सरकार में बिजली व्यवस्था पूरी तरह खराब हो गई है।

प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए

घातक : भूपेश बघेल

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ग्राम सभा के अधिकारो को उल्लंघन कर रही। एक मामले में ग्राम अलदा ग्राम सभा की अनुमति में अतिरिक्त लाईन जोड़कर फर्जी सहमति लेना बताया गया। दूसरे मामले देवरी, घुलघुल में बिना ग्राम सभा को बुलाये फर्जी सहमति बताया गया। अलदा में बालाजी स्पंज एंड आयरन लिमिटेड और देवरी घुलघुल में अग्रसेन स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना के लिए लगातार गैर-संवैधानिक एवं संदिग्ध प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। प्रभावित

गांवों के अधिकांश ग्रामीण इन उद्योगों का लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि ग्राम अलदा की ग्रामसभा के प्रस्ताव में कथित कूट रचना कर स्वीकृति प्राप्त की गई। इसकी जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तिल्ला तथा तहसीलदार-नायब तहसीलदार की समिति द्वारा की गई, जिसमें प्रस्ताव को फर्जी पाया गया। जब पूर्व उपसरपंच लखनलाल वर्मा ने इस फर्जीवाड़े का विरोध किया तो उन्हें राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा प्रताड़ित किया गया।

नीट पेपर लीक में राजनीतिक

मिलीभगत: उत्तम

रायपुर। नीट पेपर लीक मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश के 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला है। यह पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण और बड़े स्तर पर की गई मिलीभगत का परिणाम है। लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और सवाल उठाना कि पिछले नीट पेपर लीक मामलों के लिए जिम्मेदार लोगों को



सजा क्यों नहीं दी गई ऐसे पेपर आमतौर पर लीक नहीं होते। इसका मतलब है कि इसमें बड़े पैमाने पर किसी तरह की मिलीभगत है। इसमें राजनीतिक संरक्षण है। उन्होंने बताया कि 2017,2021, 2024 और अब विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि ग्राम अलदा की ग्रामसभा के प्रस्ताव में कथित कूट रचना कर स्वीकृति प्राप्त की गई। इसकी जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तिल्ला तथा तहसीलदार-नायब तहसीलदार की समिति द्वारा की गई, जिसमें प्रस्ताव को फर्जी पाया गया। जब पूर्व उपसरपंच लखनलाल वर्मा ने इस फर्जीवाड़े का विरोध किया तो उन्हें राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा प्रताड़ित किया गया।

वीबी-जी राम जी के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित हुआ सेमिनार

वीबी-जी राम जी से ग्राम पंचायतों अधिक सशक्त होगा: पासवान

रायपुर। वीबी-जी राम जी विकसित ग्राम से विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल है। यह व्यवस्था ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी को मजबूत करेगी तथा गांवों को आत्मनिर्भर और विकासोन्मुख बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। यह बात केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने अपने रायपुर प्रवास के दौरान नवा रायपुर अटल नगर स्थित नवीन सफ़िट हाउस में वीबी-जी राम जी के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित सेमिनार एवं समीक्षा



बैठक में कही। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें ग्राम पंचायतों के सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्य भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

अपने संबोधन में श्री पासवान ने कहा कि वीबी-जी राम जी आगामी एक जुलाई से देशभर में लागू किया जाएगा। वीबी-जी राम

जी ग्रामीण विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिए एक सशक्त प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के संचालन में जिन नियमों में व्यावहारिक कठिनाइयां थीं अथवा जिनमें सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, उन्हें संशोधित कर वीबी-जी

राम जी में समाहित किया गया है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब कम होगा और ग्रामीण जनता को समयबद्ध तरीके से लाभ मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वीबी-जी राम जी के माध्यम से ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त बनाया जाएगा। गांवों में विकास कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, कार्यों की पारदर्शी स्वीकृति, समय पर भुगतान, सामाजिक अंकेक्षण की मजबूती तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं के चयन को बढ़ावा मिलेगा। इससे ग्रामीण अधोसंरचना, रोजगार सृजन, जल संरक्षण, सामुदायिक

परिसंपत्तियों के निर्माण तथा आजीविका संवर्धन के कार्यों में तेजी आएगी।

उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी तथा विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीण समुदाय की भागीदारी और अधिक प्रभावी होगी। इसके साथ ही महिलाओं, स्व-सहायता समूहों और ग्रामीण युवाओं को भी योजनाओं से अधिक अवसर और लाभ प्राप्त होंगे।श्री पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार गांवों को आत्मनिर्भर, सशक्त और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सुशासन तिहार शिविरों में ग्रामीणों

को मिल रहा त्वरित समाधान

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार बलरामपुर जिले में सुशासन तिहार अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड बलरामपुर के पाढ़ी तथा विकासखंड राजपुर के गोपालपुर में शिविर आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण हेतु आवेदन प्राप्त किए गए।

पाढ़ी शिविर में सरगुजा संभागायुक्त श्री नरेन्द्र दुगगा ने कहा कि जनसमस्या निवारण शिविर ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान का प्रभावी मंच है। उन्होंने कहा कि शासन गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान



सुनिश्चित कर रहा है। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी दी गई तथा राशन कार्ड, किसान किताब एवं अन्य हितग्राही मूलक सामग्री का वितरण किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा

गोदभराई एवं अन्नप्रशन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।पाढ़ी शिविर में 221 तथा गोपालपुर शिविर में 240 आवेदन प्राप्त हुए।गोपालपुर में हितग्राहियों को आवस की चाबी, मछली पकड़ने के जाल, मृंग बीज एवं राशन कार्ड वितरित किए गए।